



पेज-2



पेज-3



पेज-6



सुविचार

यह मत भूलें कि जो शरीर व मस्तिष्क ईश्वर ने विश्व के सबसे सफल व्यक्ति को दिया है, वही आपको भी दिया है। बस आपको उसका उपयोग कैसे करना है, यह आप तय करेंगे।

## मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय समाचार पत्र आपका विश्वास

# एमपी में 10 नए मेडिकल कॉलेज और 22 आईटीआई खुलेंगे

शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी

भोपाल नप्र। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। नरोत्तम मिश्र ने कहा कि आज मध्यप्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री सीखो, कमाओ योजना लांच कर रहे हैं। यह नवाचार मध्यप्रदेश में हो रहा है। मिश्रा ने 10 मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पास किया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि यह योजना युवाओं को आत्मबल देगी, संबल देगी, रोजगार देगी और सीखकर कमाने का हुनर उनके हाथ में आएगा और हमारा नौजवान आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। आज मध्यप्रदेश में अनूठा नवाचार प्रयोग हो रहा है, सीखो कमाओ योजना का। आज नौजवानों की बात करें तो 10 नए महाविद्यालय खोलने का

प्रस्ताव कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जा रहा है। उसके लिए भी निर्देश दिए गए। चार महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 7 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषय खोलने और 589 पद स्वीकृत किए जाने का फैसला लिया है। मिश्रा ने बताया कि तकनीकी कौशल विकास विभाग द्वारा 22 आईटीआई की स्थापना करेंगे। इसके लिए कई 418 एवं 242 पदों की स्वीकृति दी गई है। गृहमंत्री ने बताया कि प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, ऊजैन, छिंदवाड़ा, बैतुल, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और सीधी जिलों के 22 विकासखंडों में न तो सरकारी और न ही निजी आईटीआई हैं। इसके लिए 34782.8 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।

यह भी हैं फैसले

- मप पाल-गडरिया-धनगर कल्याण बोर्ड का गठन।
- संत रिवादास सांस्कृतिक न्यास, भेड़ बकरी का पालन करने वाले पाल गडरिया धनगर वर्ग के कल्याण के लिए बोर्ड के गठन पर निर्णय।
- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षण प्रशासकीय स्वीकृति। धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसकी लागत 478.88 करोड़ रूपए है। सिंचाई रकबा 15031 हेक्टेयर है। 43 गांव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।
- कुडमी जाति को राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 39 में कुडमी, कुडमी के साथ शामिल किया जाना।
- सौरावीन प्रसंस्करण संयंत्र, चौराई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट और मशीनरी का स्क्रैप करने संबंधी स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव।

गृहमंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में तीन हजार रूपए की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें प्रतिमाह 13 हजार रूपए मानदेय दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 750 की बढ़ोतरी के बाद उन्हें अब 5,750 रूपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रु. सहायिका के मानदेय में 500 रु. की वृद्धि होगी।

17 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ शिवलिंग के लिए दर्शन



श्रीनगर एजेंसी। 17 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने तीसरे दिन अमरनाथ यात्रा की, जबकि 6,597 यात्रियों का एक और जत्था मंगलवार को जम्मू से घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को यात्रा के तीसरे दिन 17 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की, जबकि 6,597 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था मंगलवार सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से एक सुरक्षित काफिले में घाटी के लिए रवाना हुआ। इनमें से 4975 पुरुष, 1429 महिलाएं, 33 बच्चे, 151 साधु और 9 साधवियां हैं। यात्री या तो पारंपरिक दक्षिण कश्मीर पहलगांग मार्ग से हिमालय गुफा मंदिर तक पहुंच रहे हैं।

मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत



रांची एजेंसी। मानहानि मामले में मुश्किलों में फंसे राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत मिली है। दरअसल हाईकोर्ट ने मंगलवार चार जुलाई को सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट अब 16 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगा। बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में जनसभा के दौरान अपने एक बयान में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? राहुल गांधी के बयान के बाद उनके खिलाफ देश में अलग-अलग जगह मानहानि के मुकदमे दर्ज हुए थे।

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख का एक्सीडेंट

लॉस एंजलिस एजेंसी। किंग खान शाहरुख का अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक शूट के दौरान एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद उनके तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां ब्लाड फ्लो को रोकने के लिए एमटीए करनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक, शाहरुख के नाक में चोट लगने से खून बहने लगा। खून रोकने के लिए उनका एक छोट्टा सा ऑपरेशन करना पड़ा। हालांकि शाहरुख खान भारत लौट आए हैं और चोट से उबर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने लांच की मुयमंत्री सीखो-कमाओ योजना, युवाओं को काम सीखने और रोजगार का मौका मिलेगा

## मध्यप्रदेश के युवाओं में क्षमता प्रतिभा और टैलेंट: सीएम चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं में क्षमता, ऊर्जा, प्रतिभा और टैलेंट है। उद्योगपति और व्यापारिक संस्थान इन्हें काम सिखाएंगे, तो वे उनके प्रतिष्ठान को मालामाल कर देंगे। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और युवाओं के हितों को समान रूप से ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इससे युवाओं को काम सीखने का मौका मिलेगा और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रिस्कट मेनपावर की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।



युवाओं से मेरा प्यार, दिल और आत्मीयता का नाता

मुख्यमंत्री चौहान ने युवाओं से आत्मीय संवाद में भाव-विभोर होते हुए उन्हें आई लव यू कहा और कहा कि मेरे और आपके रिश्ते मुख्यमंत्री और हिदायती के रिश्ते नहीं हैं, मेरा आपसे प्यार, दिल और आत्मीयता का नाता है। यह स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। आप लोगों का बेहतर भविष्य बनाना हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश निर्माण को समर्पित हैं। उनके नेतृत्व में देश का गौरव बढ़ा है। वे सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं का बेहतर भविष्य कैसे सुनिश्चित हो, इस दिशा में राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए हैं। कमी क्लचर को समाप्त कर नियमित शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। छात्रवृत्तियों, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों, मेधावी विद्यार्थियों को टोपेटों, दूसरे गाँव पढ़ने जाने वाली बालिकाओं को साइकिलें उपलब्ध कराकर बेहतर और नियमित शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

कामाओ योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री चौहान रबीन्द्र भवन में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना की लांचिंग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आईटीआई उद्योग राज कुशवाहा का स्वयं योजना के पोर्टल पर पंजीयन कराकर योजना का शुभारंभ किया। चौहान ने दीप प्रज्वलित

कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश के सभी कॉलेज, स्कूल और तकनीकी शिक्षा संस्थान कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में तकनीकी

इस वर्ष शाला में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को मिलेगी ई-स्कूटी

शिक्षा, कौशल और रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुमीना सिंह, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुजया ठाकुर, खजुराहो सांसद वी.डी. शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में टाटा प्रोजेक्ट्स, वॉल्को-आयशर, सन फार्मा, ट्राइडेंट, वर्धमान टेक्सटाईल और सागर रूप के पदाधिकारी भी शामिल हुए। योजना को राज्य स्तरीय लांचिंग में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र-छात्राएँ उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी हैं। स्वतंत्रता दिवस पर एक साल में एक लाख सरकारी नौकरियों देने की बात कही गई थी। अब तक 55 हजार भर्तियाँ हो चुकी हैं और आगामी 15 अगस्त से पहले एक लाख से अधिक शासकीय भर्तियाँ हो जाएंगी।

बीजेपी कार्यकर्ता ने मानसिक विक्षिप्त पर पेशाब की, आरोपी सीधी विधायक का पूर्व प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री बोले- NS लगाएंगे

सीधी नप्र। मध्यप्रदेश के सीधी जिले में बीजेपी कार्यकर्ता ने शराब के नशे में एक मानसिक विक्षिप्त आदिवासी पर पेशाब कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो 9 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो कुबरी बाजार का है। आरोपी प्रवेश शुक्ला कुबरी का ही रहने वाला है। वह सीधी जिले से बीजेपी विधायक पं. केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि रह चुका है। सीधी एसपी रवींद्र वर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला पर केस दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधी को किसी भी काम पर नहीं छोड़ा जाएगा। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।



आरोपी पर एनएसए (नेशनल सिक्वोरिटी एक्ट) भी लगाया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि सीधी जिले में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने की कसरत का वीडियो सामने आया है। आदिवासी युवक के साथ ऐसी जघन्य और गिरी हुई हरकत का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। मध्यप्रदेश पहले ही आदिवासी अत्याचार में नंबर वन है। इस घटना ने पूरे मध्यप्रदेश को शर्मसार कर दिया है।

संविदाकर्मियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन

भोपाल नप्र। मध्यप्रदेश के करीब डेढ़ लाख संविदा कर्मचारियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर से मुक्ति मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा- मैं यह फैसला कर रहा हूँ कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। उन्होंने यह ऐलान भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आपकी दृष्टि और कार्यकुशलता नियमित कर्मचारियों से रती भर भी कम नहीं है, कई मामलों में ज्यादा है। जरूरत पड़ने पर संविदा कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों से ज्यादा काम करके दिखाया है। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराकर संविदा कर्मचारियों से कहा, बीच-बीच में थोड़ी लड़ाई हो गई थी अपनी। वेतन काट लिया था। पूछा- किस - किस का वेतन कटा हाथ उठाओ। बोले- आंदोलनों और हड़ताल के दौरान काटा गया वेतन वापस किया जाएगा।

सतना-चित्रकूट रोड पर खड़े ट्रक से टकराई बाइक तीन की मौत, चितहरा मोड़ के पास हुआ हादसा

सतना नप्र। सतना-चित्रकूट सड़क मार्ग पर सोमवार की रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है। हासिल जानकारी के मुताबिक सतना चित्रकूट मार्ग पर चितहरा मोड़ के पास सोमवार को बाइक और ट्रक के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान सीताराम कोल पिता मंगल कोल उम्र 48 वर्ष निवासी पिंडरा थाना मझगाँव, छोटेला कोल पिता चतुका कोल उम्र 56 वर्ष निवासी पिंडरा थाना मझगाँव एवं छोटेला कोल पिता गंगू कोल उम्र 28 वर्ष निवासी डंडीटोला- शुक्लावाहा थाना धारकुण्डी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि तीनों बाइक पर सवार हो कर जा रहे थे। चितहरा मोड़ पर स्थित नर्सरी के समीप सड़क पर खड़े लोड ट्रक में पीछे से उनकी बाइक टकरा गई और तीनों सड़क पर बिखर गए। ट्रकर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों के सिर फट गए और तीनों ने मौके पर ही



दम तोड़ दिया। उधर से निकले लोगों की नजर सड़क पर पड़ी बाइक और बिखरे पड़े लोगों पर पड़ी तो उन्होंने मझगाँव थाना पुलिस को सूचना दी। उस वक्त तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। बाद में बाइक के नम्बर के जरिए पुलिस ने उनके बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

माजपा विधायक ने आप नेता की कॉलर पकड़ी और थप्पड़ जड़ा

मंदसौर नप्र। मंदसौर जिले के ग्राम दलोदा में रहने वाले आम आदमी पार्टी यूथ विंग की जिलाध्यक्ष अरुण परमार ने, दलोदा थाने में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के खिलाफ आवेदन दिया है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिसिया ना बनने पर उनके द्वारा सवाल किया गया, तो विधायक जी भड़क गए। उन्होंने मेरी कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारा है। उन्हें आगे भी मारने की धमकी दी है। इसका वीडियो भी बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता अरुण परमार ने आवेदन में लिखा है, कि मेरे साथ कभी भी कोई दुर्घटना और अनहोनी हो सकती है। दलोदा थाना प्रभारी द्वारा आवेदन लेकर जांच करने का आश्वासन दिया है। वहीं विधायक और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरुण परमार द्वारा झूठ आरोप लगाया जा रहा है।

सड़क हादसा मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र की सीमा से 10 किमी दूर पलासनेर में बड़ा सड़क हादसा

9 की मौत- अनियंत्रित ट्राला वाहनों को टक्कर मारते हुए ढाबे में घुसा, मध्यप्रदेश के 7 लोग सहित 31 घायल

भोपाल नप्र। मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र की सीमा से 10 किमी दूर पलासनेर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एक अनियंत्रित ट्रक (ट्राला) ने एक मारुति कार, बस, ट्रक, पिकअप और आइसर सहित 6 से 8 बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद ट्राला ढाबे में जा घुसा। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं एमपी के 7 लोग सहित 31 लोग घायल हो गए। मौके पर महाराष्ट्र के धुलिया, शिरपुर से पुलिस बल पहुंचा है। वाहनों में दबे घायलों को निकाल कर एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार, धुले मुंबई-आगरा मार्ग पर पलासनेर गांव के पास सुबह करीब 10.30 बजे ये हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया



कि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की सीमा पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पास एक बड़ी ढलान है। ढलान पर अचानक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। इससे झड़व ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और सामने चल रहे वाहनों को टक्कर मारते हुए एक ढाबे में जा घुसा।

स्कूल के बच्चे भी हुए घायल

हादसे की सूचना मिलने के बाद दो धुलिया एसपी संजय बारकुंड मौके पर पहुंचे। एसपी बारकुंड ने बताया कि इस भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं 31 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 लोगों को धुलिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 27 लोगों का शिरपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में 4 से 5 लोग गंभीर हैं। मृतकों में 4 पुरुष, 2 महिला, एक छोटी लड़की और दो लड़के हैं। घायलों में कुछ स्कूली बच्चे भी हैं।

मृतकों के परिवार को मिलेगा 5-5 लाख का मुआवजा धुलिया कलेक्टर जलज शर्मा ने बताया कि इस सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं लगभग 31 लोग घायल हैं। इसमें से 24 लोगों का इलाज धुलिया के मेडिकल कॉलेज में करवाया जा रहा है। वहीं 7 का इलाज शिरपुर के अस्पताल में हो रहा है। मृतकों के परिजनों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से 5-5 लाख रूपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं घायलों का इलाज भी में करवाया जाएगा।

जबलपुर के बाद ग्वालियर-चंबल का दौरा

मध्यप्रदेश चुनाव कांग्रेस की स्टार प्रचारक रहेगी प्रियंका गांधी वाड़ा

भोपाल नप्र। मध्यप्रदेश में साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से बड़ी भूमिका राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा की रहने वाली है। इसके संकेत दौरे से मिलने लगे हैं। वे महाशाल का दौरा कर चुकी हैं, इसी माह उनके ग्वालियर चंबल आने की तैयारी है। राज्य में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्य प्रचारक के तौर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सक्रिय थे और उन्होंने चुनाव लड़ने से लेकर जीतने के बाद कांग्रेस सरकार के रोड में को अंतिम रूप दिया था। अब इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में शुरुआती तौर पर राहुल गांधी के स्थान पर प्रियंका गांधी की सक्रियता ज्यादा नजर आ रही है। बीते माह प्रियंका गांधी महाकौशल के जबलपुर से कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की ओर



से प्रदेशवासियों के लिए पांच गारंटी का भी भरोसा दिलाया था। एक ओर जहां राज्य कांग्रेस चुनाव की तैयारी में लगी है, वहीं राहुल नेतृत्व भी राज्य में अपना दखल बढ़ा रहा है। इस बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी मंथन किया गया। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी राज्य में चुनाव पूरी ताकत और रणनीति के मुताबिक लड़ने की तैयारी में है और प्रचार अभियान को धारदार बनाया जा रहा है, इसका प्रियंका गांधी की राज्य में सक्रियता बड़ा रहे है।



## संपादकीय

## क्यों आखिरकार राजनीति के चाणक्य अपनी ही पार्टी को संभाल नहीं पाए

आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा का हाथ थामते हुए शिंदे सरकार में शामिल हो गए। और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के भतीजे हैं अजित पवार। आखिरकार सवाल यह उठता है कि राजनीति के चाणक्य क्या अपने पार्टी के अंदर क्या चल रहा है यह समझने नाकाम रहे। दरअसल शरद पवार ने घोषणा की थी- एक मई, 1960 से एक मई, 2023 तक सार्वजनिक जीवन में लंबा समय बिताने के बाद अब कहीं रुकने पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए, मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है। इस वक्त यशवंतराव चव्हाण केंद्र के सभागार में मौजूद हर नेता के पैरों तले जमीन हिल गई थी। शरद पवार का पूरा नाम शरद गोविंदराव पवार है। पूर्व कांग्रेस नेता शरद पवार ने 1999 में अलग राह पकड़ी थी। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हैं। पवार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले शरद केंद्र में रक्षा और कृषि मंत्री रहे हैं। राजनीति के साथ-साथ वह क्रिकेट प्रशासन से भी जुड़े रहे हैं। सन 2005 से 2008 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और 2010 से 2012 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्माण का मुख्य कारण यह था कि पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा इटली मूल की सोनिया गांधी के कांग्रेस का नेतृत्व किए जाने के खिलाफ थे। इस आधार पर 20 मई, 1999 को तीनों कांग्रेस से अलग हो गए। ...और 25 मई 1999 को देश नए राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ। पवार ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस के साथ 1967 में की थी। यशवंतराव चव्हाण को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1978 में जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार बनाने के लिए उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। इस गठबंधन के फलस्वरूप वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। साल 1984 में बरामती से वह पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। 1987 में शिवसेना के बढ़ते प्रभाव की वजह से उन्होंने कांग्रेस में वापसी की। 1993 में उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री के पद शपथ ली। यह उनका सबसे विवादस्पद कार्यकाल रहा। 2001-2002 के दौरान उन पर माफिया से संबंध होने के आरोप लगे। उन पर गेहूं निर्यात और 2जी स्पेक्ट्रम घोटालों के आरोप भी लगते रहे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि शरद पवार कभी हारते नहीं हैं। जब वह खुद चुनाव लड़ते हैं तो जीत उनकी होती है। जब जीत पक्की न हो तो वह मैदान में उतरते ही नहीं। फिर भी उन्हें एक चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। यह उनके चुनावी करियर की एकमात्र हार है। बेशक यह पराजय राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान में हुई। वर्ष 2004 में उन्हें तत्कालीन अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के हाथों 'भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड' यानी 'बीसीसीआई' के चुनाव में बेहद कड़े मुकाबले में पराजय का सामना करना पड़ा। इससे वह हार नहीं माने। अगले ही साल उन्होंने डालमिया को हरा दिया और बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए।



लेखक रमेश सराफ

6

15 दलों के लोकसभा में 142 सांसद हैं। जो कुल लोकसभा सदस्यों का 16 प्रतिशत होता है। वहीं राज्यसभा में इन दलों के पास 94 सांसद हैं जो 38 प्रतिशत है। राज्यों की विधानसभाओं की कुल 4123 सीटें इन 15 दलों के पास हैं जो कुल विधानसभा सदस्यों का 42 प्रतिशत होता है। विपक्षी दलों की पटना बैठक में शामिल हुए दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस की देश के चार प्रदेशों राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में सरकार चल रही है। कांग्रेस के पास लोकसभा में 49 राज्यसभा में 19 व विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में 715 सदस्य हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल 11 करोड़ 94 लाख 95 हजार 214 वोट मिले थे।

3

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से पटना में 15 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में शामिल नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की बात कही। बैठक में शामिल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त है। जबकि जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव), झारखंड मुक्ति मोर्चा, तुणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, द्रुमक, भाकपा, नेशनल कॉंग्रेस, पीडीपी, भाकपा (माले), अपने-अपने प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त है। पटना की बैठक में शामिल 15 दलों की देश के 11 प्रदेशों में सरकार चल रही है। पिछले 9 सालों में पहली बार 15 राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर बैठकर चर्चा की है। जो देश की राजनीति के लिए आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण घटना साबित होगी। पटना में जुटे 15 दलों के लोकसभा में 142 सांसद हैं। जो कुल लोकसभा सदस्यों का 26 प्रतिशत होता है। वहीं राज्यसभा में इन दलों के पास 94 सांसद हैं जो 38 प्रतिशत है। राज्यों की विधानसभाओं की कुल 4123 सीटों में से 1717 विधानसभा सीटें इन 15 दलों के पास हैं जो कुल विधानसभा सदस्यों का 42 प्रतिशत होता है।

विपक्षी दलों की पटना बैठक में शामिल हुए दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस की देश के चार प्रदेशों राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में सरकार चल रही है। कांग्रेस के पास लोकसभा में 49 राज्यसभा में 29 व विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में 725 सदस्य हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल 11 करोड़ 94 लाख 95 हजार 214 वोट मिले थे। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी को नेता प्रोजेक्ट किया जाये। राजद नेता लालू यादव व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हैं। वहीं ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं। पटना मीटिंग में शामिल हुए नेताओं के हाथ तो जख्म मिले मगर अभी तक दिल नहीं मिल पाये हैं। मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ लाये गये अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में कांग्रेस को उनका समर्थन करने की बात कही। जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे व अरविंद केजरीवाल में बहस भी हुई। मलिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी के मंच पर इस बाबत चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्यसभा में कांग्रेस उनकी सरकार के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के खिलाफ मतदान नहीं करेगी तो भविष्य में वह किसी भी विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर नाराजगी जताई। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस जानबूझकर उनको बदनाम करने के लिए लगातार आंदोलन कर सरकार की छवि खराब कर रही है। कांग्रेस को अपने प्रादेशिक नेताओं को उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से रोकना होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में माकपा व भाकपा भी तुणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ सक्रिय है। पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस, माकपा व भाकपा ने मिलकर लड़ा था। उसके बावजूद उनका खाता भी नहीं खुल सका था। इससे तीन दलों के नेताओं को ममता बनर्जी से खासी नाराजगी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों की सरकार को हटाकर सत्ता में आई

कहना है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस जानबूझकर उनको बदनाम करने के लिए लगातार आंदोलन कर सरकार की छवि खराब कर रही है। कांग्रेस को अपने प्रादेशिक नेताओं को उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से रोकना होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में माकपा व भाकपा भी तुणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ सक्रिय है।

पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस, माकपा व भाकपा ने मिलकर लड़ा था। उसके बावजूद उनका खाता भी नहीं खुल सका था। इससे तीन दलों के नेताओं को ममता बनर्जी से खासी नाराजगी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों की सरकार को हटाकर सत्ता में आई



थी। कभी वामपंथ का गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में आज वामपंथी दलों का एक भी विधायक या सांसद नहीं है। इसके लिए वामपंथी दलों के नेता ममता बनर्जी को जिम्मेदार मानते हैं। इसीलिए उनके खिलाफ लगातार हमलावर रहते हैं। जम्मू कश्मीर में कभी नेशनल कॉंग्रेस व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक दूसरे की जानी दुश्मन होती थी। मगर दोनों ही दल अब सत्ता से बाहर हैं। इसलिए आपस में हाथ मिला रहे हैं। पीडीपी के पास तो एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में पीडीपी का एक भी सांसद नहीं जीता था। जम्मू-कश्मीर में अभी विधानसभा चुनाव होना है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने घोषणा कर रखी है कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा वह चुनाव नहीं लड़ेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर काम कर रही है। बिहार में जदयू, राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा व भाकपा की मिली जुली सरकार चल रही है। बिहार सरकार में शामिल हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने पटना बैठक से एक दिन पूर्व बिहार सरकार से अलग होकर अपनी पार्टी का समर्थन वापस ले लिया। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक झटके से कम नहीं था। वह एक तरफ तो विपक्षी दलों को एक करने में लगे हैं। वहीं उनकी सरकार में शामिल पार्टी उनको छोड़कर भाजपा नीत एनडीए में शामिल हो

जाती है। इससे नीतीश कुमार की मुहिम कमजोर पड़ती है।

पटना बैठक में बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, अन्ना द्रुमक, तुलुगु देशम पार्टी, अकाली दल, जनता दल सेवक्यूलर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहाद-उल-मुस्लिमीन, आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, मुस्लिम लीग सहित बहुत से ऐसे छोटे राजनीतिक दल जो कांग्रेस व भाजपा से समान दूरी रखकर चल रहे हैं। उनके नेता भी बैठक में शामिल नहीं हुये। इससे लगता है कि नीतीश कुमार की मुहिम अभी अधूरी है। जब तक भाजपा विरोधी छोट-बड़े सभी राजनीतिक दल एक साथ

मंच पर एकत्रित नहीं होंगे तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाना संभव नहीं होगा।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अगले लोकसभा चुनाव में कई प्रदेशों में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कही है। ओडिशा में बीजू जनता दल, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का आज भी पूरा प्रभाव नजर आ रहा है। ऐसे में 15 दलों का यह गठबंधन कैसे मुकाबला कर पाएगा। चुनाव में भाजपा के साथ इनको अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों का भी मुकाबला करने पड़ेगा।

जिसकी मीटिंग में जिस तरह से नेताओं ने हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचवाई है। यदि उसी तरह से उनके दिल भी मिल जाये तभी विपक्षी एकता सार्थक होगी। वरना तो भाजपा को हरा पाना मुश्किल ही होगा। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने करीबन 23 करोड़ वोट लेकर 303 सीटें जीती थीं। वहीं इन 15 दलों ने भी उतने ही वोट लेकर 142 सीटें ही जीत पाये थे। बराबर वोट लेकर भी आधी से भी कम सीटें जीतने का मुख्य कारण था विपक्षी वोटों का आपस में ही लड़कर बिखर जाना। इसी लिये विपक्षी वोटों का संगठित होना बहुत जरूरी है। विपक्षी दलों की एकता कितनी सिर चढ़ पाती है। इस बात का पता तो चुनावों में ही चल पायेगा।

## आयकर सर्वेक्षण के संबंध में अधिकार



नारायण जैन

भारत में कर प्रणाली हमेशा ही आम लोगों के लिए एक जटिल और अबूझ पहेली बनी रहती है। यही वजह है कि जीविकोपार्जन करने वाले लोगों से जुड़ी आयकर प्रणाली के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं होती। देश के आयकरदाता के एक बड़े वर्ग को आयकर की याद आमतौर पर जुलाई के महीने में आती है, जब टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिर समय आता है। नौकरीशुदा लोगों को अपने ऑफिस में अप्रैल के महीने में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्शन जमा करते वक्त और फरवरी में एक्यूअल इन्वेस्टमेंट डिटेल जमा करते वक्त भी इसकी याद आती है। लेकिन आयकर जमा करने वाले लोगों के एक बड़े वर्ग के लिए आयकर से जुड़ी प्रक्रिया एक जटिल पहेली के समान होती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रक्रिया को समझने की है। लोग जितना ज्यादा इस प्रक्रिया को समझेंगे, उतना ही उसमें कम गलतियां होने की संभावना बनेगी। ध्यान दें तो ज्यादातर लोगों को ये ही पता नहीं होता है कि आयकर सर्वेक्षण का तात्पर्य क्या होता है। आइए इससे जुड़े प्रावधानों, अधिकारों और अधिकारियों की शक्तियों के बारे में जानते हैं।

से संबंधित किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज कर सकते हैं। (v) आयकर प्राधिकारी किसी समारोह, समारोह या कार्यक्रम के संबंध में एक निर्धारित द्वारा किए गए व्यय की प्रकृति और पैमाने को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक जानकारी मांग सकता है। वे इस संबंध में निर्धारित या किसी व्यक्ति का बयान भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन इन अधिकारों का प्रयोग केवल समारोह या कार्यक्रम के बाद ही किया जा सकता है। आपको बता दें कि आयकर निरीक्षक के पास इन अधिकारों में से केवल उपरोक्त ( ) और ( ) के संबंध में अधिकार हैं। इस प्रकार यदि कोई निरीक्षक शपथ पर बयान दर्ज करता है या नकदी या स्टॉक सूची तैयार करता है, तो वह अपनी शक्ति से परे कार्य करता है और इसे अवैध माना जाएगा। (आयकर अधिकारी बनाम ज्वेलर्स एम्पोरियम 48 आईटीडी 164 इंदौर ट्रिब्यूनल)। सबसे अहम बात, जिसे हर आयकरदाता को जानना चाहिए, वो ये है कि आयकर अधिकारियों के पास सर्वेक्षण के दौरान किसी भी नकदी, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तुओं या चीजों को हटाने या जब्त करने का या ले जाने का अधिकार नहीं है। ऐसी शक्तियां केवल तलाशी और जब्त के दौरान ही उपलब्ध होती हैं। 2. कोई भी स्थान, जहां धर्मार्थ उद्देश्य, शिक्षा, चिकित्सा और इसी तरह की अन्य गतिविधियां की जाती हैं, का भी आयकर प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण किया जा सकता है। 3. धारा 133ए (3) के अनुसार सर्वे के दौरान अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किए गए खाते की पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार है। लेकिन आयकर निरीक्षक को यह अधिकार नहीं है। सर्वे के दौरान जब्त किए गए खाते की पुस्तकों या दस्तावेजों को रखने की अवधि 15 दिन (छुट्टियों को छोड़कर) है। इसे प्रधान मुख्य आयुक्त या निर्धारित प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है। 4. सुधा और प्रभा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी [2009] 318

आईटीआर 29 (कर्नाटक) के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 342 आईटीआर 14 (कर्नाटक) में डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की कि चूँकि जब्त करने का अधिकार कुछ दिनों के लिए है, विस्तार कुछ दिनों के लिए ही दिया जा सकता है, महीनों या वर्षों के लिए नहीं। विस्तार केवल एक बार दिया जा सकता है, बार-बार नहीं। धारा 131 के तहत यह निर्णय धारा 133ए के तहत पुस्तकों को जब्त करने के लिए भी उतना ही कारगर है। 5. धारा 133ए (2ए) के अनुसार आयकर अधिकारी टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सर्वेक्षण कर सकते हैं। अधिकारी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले व्यावसायिक परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। अति गोपनीय/व्यक्तिगत डेटा 6. टीडीएस/टीसीएस के लिए सर्वेक्षण के मामले में अनुपालन प्राधिकारियों को निम्नलिखित अधिकार नहीं है: (ए) उनके द्वारा निरीक्षण किए गए खाते की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों पर पहचान के निशान लगाने के लिए और ऐसे प्राधिकारी उद्धरण या प्रतियां नहीं बना सकते हैं। (बी) सर्वे के दौरान निरीक्षण की गई लेखा पुस्तकों या किसी अन्य दस्तावेज को जब्त करने या ले जाने का अधिकार नहीं है। (सी) ऐसे सर्वे के दौरान जांची गई या सत्यापित किसी भी नकदी, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की एक सूची बनाने का अधिकार नहीं है। 7. श्रीमती रमना रहमान बनाम यूनिवर्स ऑफ इंडिया के मामले में गौहटी उच्च न्यायालय [2004] 265 आईटीआर 16 (गौ.) में कहा गया है कि सर्वेक्षण के स्थान से दस्तावेजों, बही-खातों, फाइलों आदि को हटाकर एक अलग कमरे में ताले और चाबी के नीचे रखा जाए और कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पेपर सील लगाई जाए। तो ऐसे करण खाते की पुस्तकों को जब्त करने के समान है।

## उत्तर प्रदेश में योगीराज, सुशासन की बहार



लेखक मृत्युंजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। सरकारी तथा गैर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा रहा है। इस मुक्त भूमि पर आवास बनाकर गरीबों को दिए जा रहे हैं। अपना घर मिलने पर इन गरीबों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। होंठों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रशंसा और प्रार्थना है। प्रयागराज के लूकरगंज में 1731 वर्गमीटर की जमीन माफिया अतिक के कब्जे में थी। उसकी कीमत लगभग दस करोड़ रुपये थी। इस जमीन को 13 सितंबर 2020 को मुक्त कराया गया था। वर्ष 2021 में 26 सितंबर को मुख्यमंत्री ने यहां गरीबों के लिए आवासीय फ्लैट्स की आधारशिला रखी और मात्र 18 माह में यह आवासीय योजना पूरी हो गई। इस पर 5.68 करोड़ रुपये खर्च हुए। आवासीय योजना 1731 वर्गमीटर में विकसित की गई और इसमें दो ब्लॉक बने। गरीबों को यह फ्लैट दिये गए हैं। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। इनको बनाने में वास्तु का भी ध्यान रखा गया है। इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपना घर बना पाएँगे। लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपते वक्त मुख्यमंत्री ने फिर माफिया को सुधरने की चेतावनी दी है। वह कहते हैं पूर्ववर्ती माफिया के साथ खड़े रहते थे जबकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। 2017 से पहले गुंडे किसी की भी जमीन हथिया लेते थे। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यह

आवास मिल गया है। मुख्यमंत्री के सुशासन में अब तक माफिया के पंजों से कब्जाई गई 66,57,75 हेक्टेयर से अधिक भूमि छुड़ाई जा चुकी है। लखनऊ के पिपरसंड इलाके में भी भूमि का बड़ा टुकड़ा मुक्त कराया गया है। इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक अगस्त 2021 को न्यू स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फंक्शनल साइंस के नांव रखी थी। दो हजार करोड़ रुपये की लागत से

यह इंस्टीट्यूट बनकर खड़ा हो चुका है। स्पेशल डीजो प्रशांत कुमार का कहना है कि अब तक माफिया से 3516 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त, ध्वस्त व कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है। यह अभियान अवरत जारी रहेगा। माफिया अतिक के मोरे जाने पर प्रदेश के तमाम विरोधी दल चंडियाली आंसू बहा रहे हैं कि प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसकी वास्तविकता प्रयागराज में दिखाई दी जहां पर बिना किसी भेदभाव के पात्रता के आधार पर मुस्लिम महिलाओं को भी आवास मिला है। इस सुशासन की वजह से सपा, बसपा, कांग्रेस सहित तमाम दलों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। मायावती कह रही हैं कि परसामंद मुसलमान तो उनका वाटर है किंवचुनक यह नहीं बता पा रही हैं कि उन्होंने इनके लिए क्या किया है। यही हाल सपा का है। सपा ने मुसलमानों के नाम पर गुंडा राज कायम किया। गुंडों का सत्ता को कुर्सी सौंपी। सुशासन का दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन यह देखने को मिला है कि इस बार प्रदेश में बकरीद पर कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई और कुबानों की परंपरा भी निर्धारित स्थानों पर निभाई गई। 2017 से पहले जेलों में बंद मुख्तार अंसारी जैसे माफिया कारागार में ही बकरे की कुबानों दिया करते थे। अब जेल में बंद कोई माफिया ऐसा करने के लिए सौच भी नहीं सकता। (लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)





# बहुहित धारक सलाहकार समिति का हुआ आयोजन

दिलीप शुक्ला ✦ बड़वानी

मंगलवार को ग्लोबल ऑपच्युनिटी यूथ नेटवर्क बड़वानी के अंतर्गत ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के द्वारा बड़वानी का पहला ह्यबहु हितधारक सलाहकार समिति का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी संस्थाओं और सरकारी विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण से ग्रामीण महिलाएं एवं युवाओं को रोजगार से जोड़ना।

सर्वप्रथम दूसरा बैठक के कार्यांबुद पर किये गये कार्यों को बताया गया तथा इस वित्तीय वर्ष में युवाओं को उद्यम एवं रोजगार से बड़े अस्तर पद जोड़ने का प्लान किया गया। बैठक में कौशल प्रशिक्षण, कृषि के क्षेत्र में उद्यम, सरकारी योजनाएँ के लिए हैं उससे जुड़ाऊ, बैंक से ऋण एवं युवाओं को उद्यमिता से जुड़ने पर चर्चा किया गया। बैठक में जिला प्रबंधक



कौशल विकास ( एसआरएलएम ) निर्देशक आरसेटी, प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, बड़वानी, सह प्रधानाध्यक्ष महिला कालेज, बड़वानी, डीडीएम नाबार्ड, पशुपालन विभाग से डॉक्टर एसके गुप्ता, वानिकी विभाग से संतोष कुमार, जिला

समन्वयक खादी ग्राम उद्योग, महात्मा गांधी नेशनल फेलो, युवा उद्यमी, संचालक सेडमेप, रिलायंस फाउंडेशन से भारत, प्रवाह से हर्षा एव ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन से अनू श्री, अंकुर एवं राजू कुमार उपस्थित थे।



## भारतीय न्यायपालिका निष्पक्ष है : न्यायमूर्ति श्रीमती कन्नोजे

दिलीप शुक्ला ✦ बड़वानी

भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाया है भारतीय नागरिक न्याय पालिका में स्वयं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं न्यायपालिका के समक्ष कोई भी बड़ा नहीं है न्यायपालिका सबके लिए समान है। चाहे वह अमीर हो या गरीब भारतीय न्यायपालिका द्वारा न्याय विधान को और सहज और सरल बनाने के नागरिकों तक न्यायिक प्रणाली की जानकारी पहुंचाने व अपराध विहीन समाज के निर्माण के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। यह राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तहसील स्तर पर क्रमशः नालसा, सालसा डालसा, टालसा के रूप में कार्य करती है। विधिक सेवा प्राधिकरण से कोई भी नागरिक चाहे वह अमीर हो या गरीब निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त कर सकता है।

दिवसीय प्राचार्य प्रशिक्षण में उपस्थित जिले के शासकीय विद्यालय के 160 प्राचार्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व लीगल लिटरेसी क्लब द्वारा आयोजित विधिक कार्यशाला में न्यायमूर्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सीता कन्नोजे द्वारा कहीं गई। भारतीय न्याय प्रणाली पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालकर उपस्थित प्राचार्य से अपने आपसा हो रहे छात्र-छात्राओं या आम नागरिकों के ऊपर अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने व उसे न्यायिक जरूरतों के लिए आवश्यक विधिक जानकारी हेतु नियुक्त पीएलवी के बारे में बतलाया गया। साथ ही विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों के बारे में बतलाकर स्वस्थ समाज के निर्माण भूमिका निभाने हेतु आह्वान किया गया। जिला विधिक अधिकारी श्री दिलीप सिंह मुजाव्द ने उपस्थित प्राचार्य को पास्को एक्ट, बाल अधिकार अधिनियम, महिला सशक्तिकरण संबंधित विभिन्न कानूनों के बारे में

बतला कर जानकारी दी। साथ ही वंचित वर्गों के लिए एनजीओ के माध्यम से किस प्रकार सहायता प्रदान की जा सकती है बतलाया गया। इससे पूर्व उपस्थित न्यायमूर्ति का प्राचार्य श्रीमती रचना पुरोहित, श्रीमती नलिनी सेंगर, श्रीमती हैमलता कुरील, श्रीमती संगीता राजोरिया, श्री संतोष मिश्र, श्री प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा पुष्पहार से स्वागत किया गया। इस अवसर पर संस्था प्राचार्य श्री आर एस जाधव प्राचार्य श्री विनोद सागर, श्री अंतिम कुमार जैन, श्री अभिनव शालिय, श्री वीरेंद्र सिंह चौधरी, श्री अमृतलाल जोशी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से श्री अर्जुन परमार, शिक्षक अजय यादव, अनिल मिश्र सहित शासकीय विद्यालयों के 160 प्राचार्य उपस्थित थे। कार्यशाला का संचालन जगदीश गुजराती, प्रभारी लीगल लिटरेसी क्लब उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी द्वारा किया गया। आभार प्राचार्य श्री मनोज सेंगर द्वारा माना गया।

## 10 जुलाई से होगी बागेश्वर धाम पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा, दरबार भी लगेगा

छतरपुर, बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की संगीतमय श्री हनुमंत कथा 10 जुलाई से शुरू होने जा रही है, इस कथा में देशभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, कथा के साथ ही बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार भी लगेगा, जिसमें बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री वगैरे पृष्ठ श्रद्धालुओं को भूत, भविष्य और

वर्तमान की बातें बताएंगे। जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा जेतपुर मेट्रो डिपो, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर में आयोजित होगी, कथा के शुभारंभ से पूर्व 10 जुलाई को सुबह 8 बजे भगवा ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, इसके बाद 9 जुलाई को सुबह 8 बजे भव्य कलश यात्रा निकलेगी, इसके

बाद 10 जुलाई को शाम 4 बजे से बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की संगीतमय श्री हनुमंत कथा प्रारंभ हो जाएगी। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से लगेगा, जिसमें देशभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, दरअसल पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा कहीं भी हो, हर जगह उनकी कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।



## बदनावर की बेटी डॉक्टर खुशबू मिश्रा बनी स्त्री रोग विशेषज्ञ, पिता के सपने को किया पूरा

फ़तवा समाचार ✦ धार

अगर मेहनत सच्चे मन से की जाये तो असंभव कार्य भी संभव कर के दिखाया जा सकता है धार जिला बदनावर तहसील की बेटी कु. डॉक्टर खुशबू मुकेश मिश्रा MBBS ने पीजी स्त्री रोग विशेषज्ञ MS (Obstetrics and Gynaecology) की पढ़ाई पूरी कर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर बदनावर विधानसभा का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता श्रेय वह अपनी माता सुमन मिश्रा एवं परिवार के सदस्यों को देते हुए बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा बदनावर में हुई थी। कक्षा दसवीं में शासकीय नंदराम चोपड़ा उत्कृष्ट विद्यालय बदनावर से शिक्षा प्राप्त कर सम्पूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 10 वी कक्षा गणित विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए परंतु उनके पिता मुकेश मिश्रा का सपना था कि वह एक महिला डॉक्टर बनें। गणित में अच्छे नंबर होने के बाद भी पिता के सपने को पूरा करने के लिए बायोलॉजी (जीव विज्ञान) विषय चुना और 12वीं की पढ़ाई भी शासकीय नंदराम



चोपड़ा उत्कृष्ट विद्यालय बदनावर से प्राप्त कर जीव विज्ञान विषय में संपूर्ण धार जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर खुशबू मिश्रा बताती हैं कि 12 वीं में अध्ययन करने के दौरान देवडा सर जो कि अंग्रेजी विषय के व्याख्याता थे उन्होंने मुझे डॉक्टर बनने के लिए हमेशा प्रेरित किया। डॉक्टर खुशबू मिश्रा के पिता मुकेश मिश्रा बताते हैं कि देवडा सर एक दिन मेरे घर पर आए और मुझे कहा कि खुशबू को डॉक्टर बनने के लिए जो भी व्यवस्था आपके परिवार को करनी पड़े वह आप जरूर करें, यह लड़की रेस में दौड़ने वाले घोड़े की तरह है इसको कभी भी रोकना मत यह एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी यह बात आप मेरी लिख लेना। मुकेश मिश्रा बताते हैं कि कोरोना काल में डॉक्टर खुशबू मिश्रा ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की लगातार देखभाल की! अभी भी बदनावर में परिचित व्यक्तियों को स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्या आती है तो वह मुझे बोलते हैं तो मैं खुशबू की फोन पर बात करवा देता हूँ और खुशबू उनको सही जानकारी देकर उनकी समस्या का हल कर देती है।

डॉक्टर खुशबू मिश्रा बताती हैं कि 12 वीं की पढ़ाई के बाद में टड्डर कि शिक्षा के लिए MPPMT चयन परीक्षा की तयारी इंदौर के खरे कोचिंग क्लास से की। शासकीय गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से टड्डर की पढ़ाई कर प्रथम श्रेणी से पास हुईं। उसके बाद एक साल की इंटरशिप (बंध पत्र) के दौरान डॉक्टर खुशबू मिश्रा ने स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने के लिए द्रष्टाएण्ड की तयारी शुरू की, स्वयं से पढ़ाई कर उनका चयन NEET परीक्षा के द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञ टर (Obstetrics and Gynaecology) में करने के लिए इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर में हुआ, 3 वर्ष की उच्च शिक्षा एवं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में सेवा देने के उपरांत बुधवार, 26 जून को परीक्षा परिणाम आए जिसमें वह पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर बदनावर का नाम रोशन किया और अपने पिता का सपना MBBS & MS (Obstetrics and Gynaecology) कोर्स पूरा किया।

## जनरल स्टोर में लगी भीषण आग लाखों रुपयों का सामान जला

फ़तवा समाचार ✦ धार

शहर के पट्टा चौपाटी मार्ग पर बुधवार सुबह एक जनरल स्टोर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। प्रशासन द्वारा लगातार फायर ब्रिगेड के चार वाहनों से भी आप पर काबू नहीं पाया जा सका।

मौके पर कोतवाली पुलिस और नगर पालिका का अमले ने लगातार आग बुझाने का प्रयास किया। आग की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। बताया जा रहा है कि दुकान के नीचे कटलरी और ऊपर गोडाउन में डायपरो का बड़ा स्टॉक था जिससे आग ने भीषण रूप ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह के समय पट्टा चौपाटी स्थित हनी जनरल स्टोर से धुएँ के गुब्बार दिखाई दिए। रहवासियों ने जब धुआँ निकलते देखा तो स्टोर मालिक को इसकी सूचना दी। मालिक के पहुंचने तक आग ने



विकराल रूप ले लिया। मौके पर लगातार फायर वाहनों और नगर पालिका के टैंकों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास किए, किंतु चार फायर वाहन भी

आग पर काबू नहीं पा सका। लगातार फायर वाहनों ने पानी के तेज छिड़काव से तीन घंटे की मशकत के बाद आग पर काबू किया गया।

## सरकारी स्कूल में जनसहयोग से बनाई अंतरिक्ष लैब कौतूहल शाला

टीकमगढ़। सरकारी स्कूल के बच्चों ने अब तक अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर किताबों में ही पढ़ा होगा, लेकिन टीकमगढ़ के कुडेश्वर गांव में स्थित सरकारी स्कूल में जनसहयोग से अंतरिक्ष लैब कौतूहल शाला तैयार की गई है। यह लैब बच्चों के समक्ष अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाएगी। वगैरे सरकारी मदद के करीब तीन लाख रुपये से लैब तैयार करने का विचार जिला पंचायत सीईओ आइएएस सिद्धार्थ जैन को आया। उन्होंने इसे जनसहयोग से पूरा करा दिया। सीईओ का दावा है कि सरकारी स्कूलों में इस तरह की लैब प्रदेश में पहली है। लैब में चंद्र व सूर्यग्रहण, सौर मंडल, जॉइंटिक साइन आदि माडलस शामिल किए गए हैं। इनसे बच्चे जान सकेंगे कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, तारे क्यों

चमकते हैं, चांद और सूरज कहां छिप जाते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से खगोल विज्ञान से संबंधित साफ्टवेयर के उपयोग को भी समझाया जाएगा। लैब जिले के सभी एक हजार से अधिक स्कूलों की आठवीं तक के डेढ़ लाख बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगी। जिला मुख्यालय से पांच किलोमीटर दूर स्थित कुडेश्वर के सरकारी स्कूल में 350 वर्गफीट के भवन में दिल्ली की कंपनी द्वारा यह लैब बनाई गई है। इसमें राकेट और सेटलाइट के माडल, टेलीस्कोप, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, थ्री-डी प्रिंटर सहित अन्य उपकरण लगाए गए हैं। साथ ही अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला,

राकेश शर्मा और सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारियां लैब में संजोयी गई हैं। मंगलयान, सेटलाइट, कई तरह के एयरक्राफ्ट और रात में टेलीस्कोप के जरिए दूर आसमान से सितारे देखना बच्चों के लिए नया रहेगा।



## ग्राम पंचायत के सरपंच की भ्रष्टाचार की खबर चलने और छपने के बाद बौखलाए सरपंच ने अपने बचाव के लिए पत्रकारों पर लगाए पैसा मांगने के आरोप जिला सीईओ को दिया ज्ञापन

राम सिंह यादव ✦ टीकमगढ़

टीकमगढ़ जिले की तहसील बड़ागांव धसान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का करवाहा से ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया जिसमें ग्राम के सरपंच द्वारा जिला सीईओ को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें पत्रकारों के ऊपर झूठे आरोप जा रहे हैं तथा जिला सीईओ को खुद के बचाव के चक्कर में ग्राम पंचायत के सरपंच ने रचा षड्यंत्र जिसके चलते पत्रकारों के झूठे नाम लिखे जा रहे हैं लेकिन पैसा कुछ भी नहीं हुआ पत्रकारों ने सिर्फ सरपंच की भ्रष्टाचार की पोल खोली है जिसकी प्रशासन जांच कर सकता है बौखलाए सरपंचों ने जिला सीईओ को ज्ञापन दिया

ग्राम के लोगों का कहना है की नाली एवं पुलिया 2 माह पहले बनाई गई थी जिसमें पानी ना निकलने के कारण ग्रामीणों के दरवाजे पर पानी भर गया और मकानों में पानी भर गया जिस कारण से ग्रामीणों ने परेशान होकर अपनी समस्या पत्रकारों को सुनाई तब पत्रकारों ने यह भ्रष्टाचार की खबर प्रकाशित की गई जिस पर ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा पत्रकारों पर कई झूठे आरोप लगाए गए हैं जिसका सरपंच के पास कोई उल्लेख नहीं है जिसकी प्रशासन जांच करवा सकता है और जांच के दौरान ग्रामीणों से पूछा जाए तो सरपंच के भ्रष्टाचार की पोल खुल के सामने आजाएगी।

टीकमगढ़ जिले की तहसील बड़ागांव धसान की ग्राम पंचायत करवाहा के सरपंच की भ्रष्टाचारी की पत्रकारों ने खोली पोल



## शिवराज सरकार में कृषि विभाग कार्यालय में सोयाबीन और उड़द का टोटा कृषि विभाग कार्यालय में किसानों को नहीं मिल रहा बीज किसान परेशान 3 दिन में खत्म हो गया बीज, बिचौलियों का बोलबाला

राम सिंह यादव ✦ टीकमगढ़

पलेश: मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ओर किसानों की हरसंभव मदद करना चाहते हैं कृषि को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं लेकिन सरकार के नुमाइंदों की लापरवाही से 3 दिन में ही पलेश लहर बुजुर्ग और ग्रामीण इलाकों का बीज खत्म हो गया पलेश कृषि विभाग में शासन द्वारा भेजा गया सोयाबीन और उड़द का बीज सबसे कम मात्रा में किसानों को प्राप्त हुआ कई दिनों से किसान कृषि विभाग के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें बीज कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है कृषि विभाग में पदस्थ ग्राम सेवक और कर्मचारी अधिकारी अपना मोबाइल स्विक ऑफ कर रहे हैं जिससे किसान ग्राम सेवकों से संपर्क ना



कर सके कृषि विभाग कार्यालय खोलकर कई ग्राम सेवक कार्यालय से रफूचक्कर हो जाते हैं जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आज किसान हजारों की

संख्या में कृषि कार्यालय पहुंचे कई किसानों को बीज उपलब्ध नहीं कराया गया उनसे बोला गया है कि बीज समाप्त हो गया है जब शासन से ही आया तब जाकर दिया जाएगा क्षेत्रीय किसानों

ने मांग की है कि शासन द्वारा कितना बीज कृषि विभाग पलेश को उपलब्ध कराया गया कितना कर्मचारियों के द्वारा बांटा गया उसकी जांच होना चाहिए



## यात्री बसों में नियमों की अनदेखी : कुछ के इमरजेंसी डोर जाम, कहीं शो-पीस बने फायर सिस्टम

फतवा समाचार ✦ जबलपुर

महाराष्ट्र के बुलढाणा में हाईवे पर यात्री बस में लगी आग में 26 लोग जिंदा जल गए। यह दुर्घटना होलनाक थी जिसने अहसास करा दिया है कि ऐसा हादसा यदि अभी नहीं चेते तो आसपास कभी भी हो सकता है। जबलपुर में तो हालत यह है कि यात्री बसों को सवारी ढोने का साधन बस समझा जाता है। इन बसों में सुरक्षा के जो मानक होते हैं उसकी हर स्तर पर अनदेखी हो रही है। परिवहन विभाग जिसको इन बसों में सभी तरह के मापदण्डों का पालन

हो इसकी मॉनिटरिंग के साथ कार्रवाई करना है वह विभाग देखा जाए तो बीते कई सालों से खानापूर्ति ही कर रहा है। जब कभी हादसा हुआ तो कुछ सक्रियता दिखाई जाती है लेकिन जैसे ही मामला ठण्डा हुआ तो सब कुछ पुगने ढर्रे पर आ जाता है। जबलपुर में 1200 अलग-अलग तरह की बसें पंजीकृत हैं, जानकारों का कहना है कि इनमें से मुश्किल से कुछ बसें ही सुरक्षा मानक पूरे कर रही होंगी वह भी तब जब ये जांच के लिए खड़ी कर ली जाती है। शेष में सब कुछ कागजों में बेहतर है मौके पर नहीं।



मौके पर कुछ ऐसे मिले खालत

कन दूरी की बसों में इमरजेंसी दरवाजे पर कहीं ताला लटका हुआ है, तो कहीं आपात स्थिति आ जाए तो वह दरवाजा खुल ही नहीं सकता, क्योंकि वह सालों से जाम है। इसी तरह फायर सेफ्टी सिस्टम फायर अलार्म बने मापदण्डों में बसों में लगाया है। अग्निशमन यंत्र रखना जरूरी है लेकिन ये यंत्रों की खालत में नहीं है। मौके पर ट्राफी को इमरजेंसी दवाई दी जा सके इसके लिए फर्स्ट ऐड किट जरूरी है पर ज्यादातर के पास यह नहीं है। इस तरह बसों में जो एकदम शुरुआती सुरक्षा मानक होते हैं वे तक गुंता दिये गये हैं।

इनमें सीट बढ़ाने की होड़ लगी

जबलपुर से नागपुर, जबलपुर से भोपाल, रायपुर, देवर, झांझार, बिलासपुर, रीवा जैसी कुछ लंबी दूरी पर चलने वाली बसों में सीट को स्तूप बनाकर की होड़ में इमरजेंसी दरवाजा और अन्य संसाधनों को दरकिनार कर बस सीट बढ़ा दी गई है। ऑल इंडिया परमिट की इन बसों में ज्यादा सीटें बढ़ाई जा सकें इसके लिए हर तरह का जतन है। प्रायद्वीप के समय ट्राफी की जाम कैसी बवेगी इसकी और किसी का ध्यान नहीं है। इन बसों में पार्सल ढोने सामान रखने की जगह है पर इमरजेंसी दरवाजे को दूरत खुलने वाली खालत में नहीं देखा जा सकता है।

## मुख्यमंत्री युवा इंटरनेशनल योजना बैच 2 : जिले से 90 युवाओं का किया जाएगा चयन

कमलेन्द्र पटेल ✦ कटनी

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री युवा इंटरनेशनल योजना के बैच 2 का शुभारम्भ किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के 'छीरल्ल' स्मृतदर के मंडल पर आधारित मुख्यमंत्री युवा इंटरनेशनल फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम मध्य प्रदेश कडकड मध्यप्रदेश सरकार की एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव योजना है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को अपना कौशल बढ़ाने, प्रोफेशनल वातावरण में कार्य करने और मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रूप में प्रदेश के विकास में योगदान देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक विकासखंड में 15 इंटरनर्स, प्रदेश भर में कुल 4695 युवाओं चयन किया जाएगा। योजना के तहत कटनी जिले से 90 इंटरनर्स (सीएम जन सेवा मित्र) का चयन किया जाएगा। जिनको इस योजना के तहत विकास योजनाओं का कार्य अनुभव दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा इंटरनेशनल योजना में 2 जुलाई से 10



जुलाई 2023 तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम <https://services.mp.gov.in/main/citizen/services/ui#intr/apply> आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए पिछले 2 वर्षों में न्यूनतम 50 प्रतिशत से स्नातक, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। इस योजना के द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र बनने का मौका मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 8 हजार रुपए का स्टायपेंड दिया जायेगा एवं इंटरनेशनल की कार्यविधि 6 माह की होगी।

## जिले में अब तक 229.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

कमलेन्द्र पटेल ✦ कटनी

कटनी जिले में इस वर्ष 1 जून से 4 जुलाई की प्रातः तक की अवधि तक कुल 229.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। जबकि बीते वर्ष इसी अवधि के दौरान 146.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। इस प्रकार इस साल पिछले वर्ष की तुलना में 183.4 मिलीमीटर अधिक वर्षा दर्ज की गई है।

अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल अलाउच्य अवधि तक वर्षा मापी केंद्र कटनी में 187.6 मिलीमीटर, रीठी में 219.2 मिलीमीटर, बड़वावा में 230.6 मिलीमीटर, बरही में 152.0 मिलीमीटर, विजयराघवगढ़ में 120.3 मिलीमीटर, बहोरीबंद में 195.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसी प्रकार स्लीमनाबाद में 360.8 मिलीमीटर एवं दोमरखेड़ा में 371.7 मिलीमीटर वास्तविक वर्षा दर्ज की गई।

पिछले साल की तुलना में इस वर्ष हुई 183.4 मिलीमीटर अधिक बारिश

## कृति का आनंद लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे सहस्रधारा, यहां दिखता है मां नर्मदा का रौद्र रूप

बर्गीबांध के भराव के कारण यहां की धारा और जलप्रपात की संख्या काफी अधिक हो गई है, माना जाता है कि मानसून के समय मां नर्मदा का रौद्र रूप यहां दिखाई देता है।

फतवा समाचार ✦ मंडला

मानसून लगते ही मध्यप्रदेश के मंडला जिले में स्थित सहस्रधारा का नजारा देखने लायक है। लोगों की लंबी कतार यहां प्रकृति का अनोखा नजारा देखने उमड़ रही है। नैसर्गिक स्थल सहस्रधारा के नाम से पहचाने जाने वाला यह स्थान मंडला जिले की एक अनुपम धरोहर के रूप में पर्यटन स्थल है। मानसून लगते ही यहां का नजारा और जलप्रपात पहाड़ियों से निकलने वाली धाराएं काफी आकर्षण का केंद्र होती हैं, यहां बड़ी संख्या में लोग फोटो लेने पहुंचते हैं। बर्गी बांध के भराव के कारण यहां की धारा और जलप्रपात की संख्या काफी अधिक हो गई है। यह स्थान बर्गी बांध के भराव का आखरी पॉइंट है। इस स्थान का पुराणों में भी उल्लेख किया गया है। पौराणिक मान्यता के



अनुसार यहां हंस वंशी राजा कार्तवीर्य अर्जुन थे जिन्हें सहस्रबाहु से भी जाना जाता है, मां नर्मदा का रौद्र रूप यहां देता है दिखाई देता है। सहस्रधारा में दो प्राचीन मंदिर हैं जिसमें पहला शिव मंदिर और दूसरा सहस्र बाहु जी का मंदिर है। शासन द्वारा इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया है, यहां के सुंदर दृश्य को देखने के लिए दूरदराज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।

## मेरा बूथ सबसे मजबूत, के तहत विशाल सम्मेलन का हुआ आयोजन

दुर्गेश बर्मन ✦ डिंडोरी-शाहपुरा

जिला अध्यक्ष अवधराज बिलैया,के निदेशानुसार ,मंडल अध्यक्ष घनश्याम कछवाहा के नेतृत्व में मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत भोपाल से आये अनिल राम , की अध्यक्षता में नगर के मानस भवन में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया ,सम्मेलन के शुरुआत में आगंतुकों के द्वारा सर्वप्रथम भारत माता के तैलीय चित्र पर दीप प्रज्वलन किया गया इसके बाद सम्मेलन को जनपद अध्यक्ष प्रियंका मरावी,सोमन मरावी सरपंच,सोनलाल परस्ते महामंत्री, अनूप गुप्ता, ज्ञानदीप त्रिपाठी, मनोहर सोनी,के द्वारा संबोधित किया गया , सम्मेलन के दौरान अनिल राम बूथ विस्तारक ने बताया कि भाजपा पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है इस पार्टी में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और सदस्य है,ये संभव हुआ है कार्यकर्ताओं से ,इसी क्रम में पार्टी के द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया।

यदि बूथ जीत गए तो विधानसभा जीतना बहुत आसान है , हमे मिलकर सारे बूथ को मजबूत करना है सभी सक्ति केंद्रों में लगातार बैठक करना है जिससे अधिक से अधिक लोगों से सीधा जुड़ाव होगा साथ ही सरकार की योजनाये आसानी से लोगों तक पहुंचेगी ,इस दौरान अनिल राम ,बसंत गुप्ता वरिष्ठ नेता,जिला महामंत्री ज्ञानदीप त्रिपाठी, जिला

## नगर के मानस भवन में आयोजित हुआ सम्मेलन



उपाध्यक्ष मनोहर सोनी, अनूप गुप्ता जिला सह मीडिया प्रभारी,प्रियंका आर्मां जनपद अध्यक्ष, राहुल रेकवार संसद प्रतिनिधि, गिरजा कारपेंटर प्रदेश कार्य समिति सदस्य ,सोनलाल परस्ते ,सुरेंद्र साहू मंडल महामंत्री,उत्तम असादी, रामकुमार परस्ते,बाबा ठाकुर, राजेश साहू,रामलाल रजक,अरविंद रजक,दिलीप झांरिया,राजेन्द्र तिवारी,पवन

साहू उपाध्यक्ष, अर्जुन झांरिया,अजमेर तेकाम ,सोमन मरावी,पवन झांरिया,अयोध्या सोनी,मन्नु लाल साहू,हरीन्द्र मरावी ,हैरालाल साहू,गोल् गुप्ता, सोमन झांरिया,शांति लाल साहू,पुणेंद्र तेकाम,कृष्णलाल सोनी,बूथ अध्यक्ष, महामंत्री,बीएनओ,पन्ना प्रमुख व अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी गण मौजूद रहे ।

## सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को जल्द सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता डॉ नूपुर धमीजा ने उठाई जिम्मेदारी

फतवा समाचार ✦ कटनी

सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एवं नारी शक्ति एक नई पहल संस्था की संस्थापक डॉ नूपुर धमीजा को जैसे ही सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की जानकारी प्राप्त हुई तो उनके द्वारा नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन जिला सिंगरौली की जिलाध्यक्ष किरण सिंह को तत्काल निर्देशित किया गया एवं तुरंत पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी प्राप्त कर संस्था को भेजने के लिए कहा गया।

जिस पर सिंगरौली जिला अध्यक्ष किरण सिंह के निर्देश पर सिंगरौली लाइजनिंग ऑफिसर विनोद सिंह एवं शशि पाल सिंह के द्वारा पीड़ित परिवार के घर जाकर पीड़ित परिवार से संपर्क कर घटना की पूरी



जानकारी ली गयी। जहां पर पीड़ित परिवार ने संस्था के नाम एप्लीकेशन देते हुए संस्था से आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाए जाने का सहयोग मांगा जिसके बाद नारी शक्ति एक नई पहल संस्था की संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता डॉ नूपुर धमीजा ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए निशुल्क कानूनी सहायता देने का फैसला किया है और जिसमें संस्था की ओर से जिला न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने के लिए संस्था की ओर से निशुल्क एडवोकेट पीड़ित परिवार को दिए जाने का फैसला किया गया। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक संस्था के द्वारा निः शुल्क रूप से पीड़ित परिवार की लड़ाई लड़ी जाएगी एवं न्याय दिलाया जाएगा।

## जीवित पिता को बताया मृत और पा ली अनुकम्पा नियुक्ति

फतवा समाचार ✦ जबलपुर

कलेक्ट्रेट के कार्यालय सहायक आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग में एक कर्मचारी ने करीब 35 वर्ष पहले अपने जीवित पिता को मृत बताकर अनुकम्पा नियुक्ति पाई थी। जबकि उसके पिता कलेक्ट्रेट के कर्मचारी ही नहीं थे। इस प्रकार कर्मचारी ने फर्जीवाड़ा किया और अब कलेक्ट्रेट के ही एक कर्मचारी ने इस मामले की शिकायत जनसुनवाई में करते हुए कार्रवाई की मांग की है। जनजातीय कार्य विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी पूरन सिंह जाटव ने जनसुनवाई में लिखित शिकायत दी कि गौतम सेनगुप्ता सहायक ग्रेड-3 ने अपने जीवित पिता सुनील वरन सेनगुप्ता को मृत बताकर 24 फरवरी 1988 को फर्जी अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर ली थी। उसके पिता किसी भी विभाग में नहीं थे।



इस मामले में अपर कलेक्टर ने फौरन जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता राहुल पटेल ने जनसुनवाई में शिकायत दी कि उजार पुरवा में जागृति प्राथमिक

उपभोक्ता सहकारी भंडार के संचालक द्वारा मनमानी की जा रही है। राशन दुकान कभी भी समय पर नहीं खुलती है। राशन की कालाबाजारी की जाती है।

शिकायतकर्ता राहुल कनौजिया ने शिकायत दी कि दाना गोदाम पुराना बस स्टैंड के एक दुकान संचालक ने बिजली के पोल को अपनी दुकान के अंदर कर लिया है। शोध ही कार्रवाई की मांग की गई है।

सबकी हुई सुनवाई: जनसुनवाई में प्रभा यादव ने बताया कि उनका राशन कार्ड नहीं बना है। उन्होंने आवेदन दिया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जनसुनवाई में प्रभा यादव के राशन कार्ड के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। पन्ना लाल ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर आय प्रमाण-पत्र एवं कान पर विभागीय अधिकारियों ने कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर मिशा सिंह, विमलेश सिंह, शेर सिंह मीणा, सहायक आयुक्त आनंद जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

दो साल से बंद पड़ा है नल जल योजना,आवेदन के बाद भी नहीं हो रही कार्यवाही

## नहरों के सीपेज से किसानों के सैकड़ों एकड़ जमीन बन जाती है दलदली और अनुपयोगी

दुर्गेश बर्मन ✦ कटनी

शासन की अनेक योजनाएं होने के बावजूद अनुसूचित जनजाति क्षेत्र डिंडोरी के किसान आधारभूत चीजों के मोहताज हैं। कारण स्पष्ट है योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है। प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और लगता है मध्यप्रदेश शासन जनसमस्या समाधान हो इसमें रुचि नहीं ले रही है। भारतीय किसान संघ क्षेत्र के किसानों की समस्या को लगातार सामने ला रही है, चुनावी वर्ष है इसके बाद भी शासन प्रशासन के लोग जन समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं बाकी समय किसानों को कौन सुनेगा। भारतीय किसान संघ के ग्राम इकाई ग्राम पंचायत बिजौरी में जनसमस्या के संबंध में आज बुधवार को जिलाध्यक्ष बिहारी लाल साहू की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में नहर आया है किन्तु लापरवाही पूर्वक बने नहर जगह जगह लीक होते हैं जिससे सैकड़ों एकड़ के किसान रबी की फसल नहीं ले पाते हैं,वही ग्राम में बिजली की विकट समस्या है



सिर्फ एक फेस बिजली से काम चला रहे हैं जिससे वोल्टेज हमेशा लो बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि नल जल योजना 01 माह चलने के बाद पड़ी हुई है प्रशासनिक इकाई ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है और फ्लोराइड युक्त विषैला पानी पीना पड़ता है। भारतीय किसान संघ ने विगत दिनों बजाग तहसील अंतर्गत भुरसी ग्राम पंचायत के पोषक ग्राम टूडटोला में बिजली नहीं होने से ग्रामीणों को हो रही समस्या को सामने लाया ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया किन्तु कलेक्टर डिंडोरी का कहना है बिजली के सिर्फ

बिजली तार और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 08 लाख का खर्चा आएगा किंतु प्रशासन के पास कोई फंड नहीं है जिससे किसानों के समस्या का समाधान हो सके वही मुख्यमंत्री का कहना है कि बिजली समस्या का 24 घण्टे में समाधान होगा।आजादी के बाद भी लोग बिजली को मोहताज है अंधेरे में जीवन जी रहे हैं इनकी सुध कोई लेगा, या लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बिना बिजली के जीवन यापन करते रहेंगे। आज के चौपाल में भारतीय किसान संघ के किसान नेता जिलाध्यक्ष बिहारीलाल साहू, जिलामंत्री में अधिवक्ता निर्मल कुमार साहू,तहसील मंत्री अधिवक्ता लवकुश झांरिया सहित ग्राम बिजौरी के सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित रहे है।



दिल्ली हो या मुंबई, हैदराबाद हो या रीवा, हर जगह कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र लगाए जा रहे हैं

# रीवा में कचरे से पैदा होगी 12 मेगावाट बिजली

फ़तवा समाचार ◆ रीवा

शहरों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण के साथ ही इससे खाद और बिजली बनाने का काम अभी जोरों पर है। दिल्ली हो या मुंबई, हैदराबाद हो या रीवा, हर जगह कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। रीवा जैसा छोटा शहर भी कचरे से 12 मेगावाट बिजली पैदा करने की तैयारी में है। यह काम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आरईएसएल (आरईएसएल) के कंधों पर है। कंपनी अब दिल्लीवासियों को कूड़े के पहाड़ से निजात दिलाना चाहती है। आरईएसएल ने ग्रेटर हैदराबाद नगरनिगम के साथ मिलकर पिछले 12 वर्षों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ऐसा कमाल दिखाया है कि महानगर को स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 में कचरा मुक्त शहर के लिए श्री स्टार मिल चुका है। आरईएसएल के सीईओ मसूद मलिक ने बताया कि हमारे स्टेशनों तक पहुंचा कूड़ा कभी

बाहर नहीं जाता। यानी कूड़े को किसी-न-किसी रूप में इस्तेमाल लायक बना दिया जाता है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के विभिन्न इलाकों से रोजाना 6,000 टन कूड़ा उनके विभिन्न ट्रांसफर स्टेशनों में पहुंचता है। मसूद मलिक बताते हैं कि आरईएसएल के निपटान स्थलों में सूखे कचरे से खाद बनाया जाता है तो कूड़े से प्लास्टिक को अलग करके उससे अस्पतालों के लिए प्लास्टिक बैग बनाया जा रहा है। साथ ही गीले कचरे को बिजली में बदलने के लिए आरडीएफ प्लांट में डाला जाता है। कंपनी ने विभिन्न शहरों में कचरे से कुल 175 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें अकेले हैदराबाद से 100 से 115 मेगावाट बिजली पैदा होगी। जवाहननगर प्लांट से 24 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई है और यहाँ अतिरिक्त 24 मेवा एडवांस स्टेशन में है। यह दक्षिण भारत का पहला और सबसे बड़ा अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र है।



## दिल्ली में 14 मेवा बिजली का उत्पादन शुरू

दिल्ली के बढाना प्लांट में कचरे से 14 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है। इसी प्लांट से अतिरिक्त 36 मेगावाट बिजली उत्पादन की भी योजना है। आरईएसएल के कॉर्पोरेट प्रमुख रमेश बिना ने बताया कि मध्यप्रदेश के रीवा में पहले चरण में कचरे से 6 मेगावाट बिजली बनाने का काम अंतिम चरण में है। रीवा प्लांट में अतिरिक्त 6 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। इसी प्रकार मुंबई के देवनगर में अपशिष्ट से 8 मेगावाट बिजली पैदा होगी। नोएडा में थ्रस्ट फिट गैट सुपरटेक टिडन टॉवर के कचरे को हटाने और इसे रिसाइल करने का काम भी आरईएसएल ही कर रही है।

## गोरइया में पट्टेमालिक की जमीन पर दबंगों ने जौतकर किया कब्जा

श्रीधर सिंह ◆ सतना

जिले के कोटर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरइया में फरियादी किसान बेबी खातून पति मो. शब्बीर की आराजी नंबर 1014/1/1/1/1, 1014/1/1/1/2, 1014/1/2/1, पर गांव के दबंग रतिभान सिंह, नीरज सिंह, बृजेश सिंह, मांडवी, आसिमा सिंह, मो. शब्बीर, मो. मो. नईम, मो. फईम उर्फ लालू, मो. सहीम, एकजुट होकर जबरन गुंडागर्दी के दम पर दो तीन ट्रेक्टर लेकर खेत की जुताई कर रहे हैं जब फरियादी किसान की जानकारी हुई कि उसकी जमीन जाती जा रही है तब खेत जाकर देखा तो कुछ दबंग उसके खेत की जुताई कर रहे थे उस फरियादी किसान मो. शब्बीर ने खेत जोतने से मना किया कि यह मेरा खेत है क्यों जबरन जोत रहे



कोटर थाना में किसान ने लगाई गुहार।

दबंगों द्वारा लाठी डंडों और फरसा से जान से मार देने की देर घमकी।

हो इतने में दबंग लोगों ने गाली-गलौज और लाठी डंडा लेकर किसान पर हमला कर दिया किसान किसी तरह जान बचाकर भागा और कोटर थाना आकर लिखित शिकायत की कि साहब गांव के ही कुछ दबंग मेरी जमीन जोत रहे हैं मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

# अकौन में पदस्थ सहायक सचिव की मनमानी से ग्रामीण हो रहे परेशान

श्रीधर सिंह ◆ सतना

कोटर तहसील क्षेत्र के अकौना ग्राम पंचायत में पदस्थ सहायक सचिव आरती सिंह के कारण ग्रामीण परेशान है ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा राशन से भी वंचित है लोग यहां पर सहायक सचिव आरती सिंह है जिसकी वजह से काम भी नहीं होते हैं उन को कॉल किया जाए तो फोन भी रिसेव नहीं करती है जिसके कारण ग्रामीण परेशान है जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच श्रद्धा सिंह ने बताया कि इसके लिए रोजगार सहायक को कई बार बोला गया है कि ग्राम पंचायत में हफ्ते में 2 से 3 दिन का समय दे लेकिन वह आती नहीं है कुल मिलाकर कहा जाए तो रामपुर जनपद सीईओ अशोक तिवारी से भी इनकी शिकायत की जा चुकी है लेकिन उनकी उदासीनता के चलते रोजगार सहायक ग्राम पंचायत से नदारद रहती हैं इसके लिए ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग 181 में भी शिकायत दर्ज करा कर और जांच करने की मांग की है कि जो भी कार्य हुए हैं उनकी भी जांच की जाए क्योंकि रोजगार सहायक घर बने नहीं और प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे भी निकाल दिए हैं उसके साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि गरीबों के पैसे भी मजदूरी के आज तक नहीं निकाली जिससे लोग परेशान हो रहे हैं



रोजगार सहायक की हुई कलेक्टर से शिकायत

अकौना ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक आरती सिंह के खिलाफ ग्राम पंचायत के सरपंच श्रद्धा सिंह द्वारा सतना कलेक्टर से शिकायत कर-के और आरोप लगाया गया कि वह ग्राम पंचायत से तेना-देना नहीं रखती और ना ही आती है इनको तत्काल यहां से हटाकर और दूसरा सहायक सचिव नियुक्त किया जाए जिससे लोगों के काम ना रुके इन पर राजनीति संरक्षण प्राप्त होने की वजह से यह ग्राम पंचायत नहीं आती और लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है

छ माह से नहीं मिली मजदूरी का पैसा

बर्दी वर्ग ने आरोप लगाया है कि सहायक सचिव की मनमानी की वजह से मजदूरी का पैसा नौरे खाते में नहीं बल्कि किसी दूसरे के खाते में डाल दिया गया है जिसके लिए मैं 6 माह से ग्राम पंचायत के चक्कर लगा रहा हूं लेकिन कोई सुबने को तैयार नहीं है इसके लिए सरपंच से बोले तो सरपंच ने ग्राम पंचायत के सहायक सचिव को कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही है बोल रही है आपका पैसा आ जाएगा लेकिन छ माह लेने के बाद अभी तक अक्रांट में पैसा नहीं आया? बरसात का मौसम है काम भी नहीं है किसी तरह मजदूरी करके अपना काम चला रहा हूं लेकिन सहायक सचिव की मनमानी से मेरा पैसा भी नहीं आया है।

अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश

## साप्ताहिक जनसुनवाई में 62 आवेदकों की हुई सुनवाई जिपि. सीईओ, संयुक्त कलेक्टर सहित अधिकारियों ने सुनी समस्याएं

फ़तवा समाचार ◆ अनूपपुर

आम जन की समस्याओं के निराकरण के तहत कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई में 62 लोगों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभय सिंह आहिरिया, संयुक्त कलेक्टर श्री अजीत तिकरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं को सुना तथा उनके आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की। उल्लेखनीय है कि आम जन की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक मंगलवार को राज्य शासन के दिशानिर्देशानुसार कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें जिलेभर के लोग अपनी समस्याओं को आवेदन के साथ प्रस्तुत करते हैं। जनसुनवाई में मौके पर ही कार्यवाही होने से आम जन में सुनवाई के प्रति भरोसा कायम हुआ है। आज जनसुनवाई में ग्राम खमरोध विकासखण्ड कोतमा की रानी प्रजापति ने ग्राम पंचायत खमरोध के आंगनवाड़ी केन्द्र क्र. 50 में सहायिका पद हेतु जारी अंतिम सूची के विरुद्ध दावा आपाति प्रस्तुत करने, वार्ड क्र. 03 अनूपपुर के निखिल कुमार प्रजापति ने पट्टे की जमीन पर बनाए जा रहे मकान को दबंगों द्वारा अवरोध उत्पन्न किए जाने, ग्राम बरगावां के सुनील कहार ने विद्युत बिल में सुधार न होने, ग्राम बिजौड़ी



पोस्ट पसला के विनोद कुमार केबट ने ग्राम पंचायत बिजौड़ी द्वारा कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर रिपेयरिंग कार्य के बिल का भुगतान नहीं करने, ग्राम अचलपुर तहसील पुष्पराजगढ़ के राजेन्द्र कुमार सत ने उद्यानिकी विभाग योजना अंतर्गत पीएमएफएमई के सॉक्सडी राशि और ब्याज के संबंध में, ग्राम तितरीपोड़ी जिला अनूपपुर के सुखलाल सिंह ने कैसर के ईलाज हेतु मदद किए जाने, ग्राम घुईदादर थाना राजेन्द्रग्राम की सुखमत बाई टेकम ने पति द्वारा परिवार के पालन-पोषण हेतु गुजारा भत्ता दिलाए जाने, वार्ड नं. 15 जैतरी की राधा राठी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ दिलाए जाने सहित 62 आवेदन प्रस्तुत किए गए।

## ओरियंट पेपर मिल द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के जिला पार्षद ने सौंपा ज्ञापन

फ़तवा समाचार ◆ अनूपपुर

शहडोल जिले के सीमावर्ती क्षेत्र संचालित ओरियंट पेपर मिल के द्वारा काफी लंबे समय से प्रदूषण फैलाया जा रहा है जिसको लेकर नगर परिषद बरगां अमलाई वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद सौरभ कोरी ने संभागायुक्त कार्यालय जाकर वार्ड वासियों क्षेत्र वासियों की जन समस्याओं से अवगत कराया जिस पर प्रमुखता पार्षद के द्वारा बताया गया कि विगत कई वर्षों से कारखाने से क्लोरीन गैस का रिसाव एवं केमिकल युक्त पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है जिसकी जानकारी जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बावजूद ना तो किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है और ना ही ओरियंट पेपर मिल के



प्रबंधन के द्वारा उस पर रोकथाम लगाया जाता है जिसको लेकर सौरभ गोरी ने शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा को ज्ञापन देते हुए सारी समस्या से अवगत कराया जिसमें पार्षद ने बताया ओरियंट पेपर मिल एवं सोडा फैक्ट्री के द्वारा क्लोरीन गैस एवं केमिकल युक्त कचरा

(चूना वा राखड़ ) वातावरण में फैलने के कारण स्वास्थ्य संबंधित बीमारी एवं सांस लेने में तकलीफ होती है ओरियंट पेपर मिल के द्वारा कामज बनाने की क्रिया में संलग्न पल्प मिल एवं ऐसे अन्य प्लांट से निकला हुआ। जहरीला केमिकल युक्त पानी एवं सोडा फैक्ट्री के द्वारा कार्टिक वाटर एवं अन्य दुर्गंध युक्त अपशिष्ट को सीधा सोन नदी में छोड़ा जा रहा है जिससे आसपास के क्षेत्र के मवेशी एवं मानव सहित जलीय जीव जंतु उक्त पानी का सेवन करने से गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है उक्त जल का उपयोग स्थानीय कुषकों के द्वारा कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जाता है जिससे कृषि योग्य भूमि की उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती है और भूमि बंजर एवं कठोर हो जाता है।

## हत्या के मामले में पत्नी को उम्र कैद की सजा प्रेमी के साथ मिलकर छिपा दिए थे सबूत

फ़तवा समाचार ◆ सतना

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में सतना कोर्ट के प्रथम श्रेणी के विद्वान न्यायाधीश ने पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं सबूत छिपाने के मामले में बनाए गए आरोपित प्रेमी को भी पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सतना यतेंद्र कुमार गुरु ने गत जनवरी 2021 में हुई शैलेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी उत्तरी पतरी सतना की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सपना सिंह और उसके प्रेमी कमलेश सिंह पिता अरविंद सिंह निवासी ग्राम पवैया कोठी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी सपना सिंह को आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि कमलेश सिंह को 5 साल की कैद के साथ एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण की एडीपीओ बीएन शर्मा ने पेश की है।

यह थ मामला : लोक अभियोजन के अनुसार, मृतक शैलेन्द्र सिंह शराब दुकान में तबौर सेल्समैन काम करता था और शहर के उत्तरी पतरी में अपनी पत्नी सपना सिंह के साथ रहता था। गत 24 जनवरी 2021 की सुबह वह दुकान के लिए निकला, लेकिन लौटकर वापस



नहीं आया। उसके मोबाइल फोन भी स्विक ऑफ थे। लिहाजा 25 जनवरी को उसके पिता देवेंद्र सिंह ने सिविल लाइन थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी तलाश जारी ही थी कि इसी बीच 31 जनवरी को कोठी निवासी देवेंद्र श्रीवास्तव ने कोठी पुलिस को उसके होटल के पास पाइप लाइन के लिए खोदी गई नाली में किसी के शव पड़ा होने की सूचना दी। पुलिस ने शव को शिनाख्त कराई तो पता चला कि वह शव शराब दुकान के सेल्समैन शैलेन्द्र सिंह भदौरिया की है। पुलिस जांच के दौरान

## पेशाब कांड के आरोपित के घर पर कानून के हिसाब से चलेगा बुलडोजर : नरोत्तम मिश्रा

फ़तवा समाचार ◆ सीधी/भोपाल

सीधी जिले में मानसिक रूप से विशिष्ट आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले को लेकर राजनीति गरमा रही है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इस प्रकरण में आरोपित के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष की मांग पर प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट किया कि आरोपित के घर पर कानून के हिसाब से बुलडोजर चलाया जाएगा, न कि विपक्ष के अनुसार।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने बुधवार को सुबह मीडिया से बातचीत में कहा कि जब घटना सामने आई, तो तुरंत कार्रवाई की गई। आरोपित प्रवेश शुक्ला को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। वह पुलिस की हिरासत में है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है और उस पर एनएसए लगेगा। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की आरोपित के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग संबंधी सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के हिसाब से बुलडोजर नहीं चलेगा। कानून के हिसाब से बुलडोजर चलेगा। अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर चलेगा। जहां भी अतिक्रमण होता है, वहां कानून अपना कार्य करता है।

दरअसल, मंगलवार को सोशल मीडिया

कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की मांग पर प्रदेश के गृहमंत्री ने सी प्रतिप्रिया



पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए दिख रहा था। मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मंगलवार को रात ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर एनएसए भी लगाया गया है। आरोपित प्रवेश शुक्ला क्षेत्रीय भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि रह चुका है। वह सीधी जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर कुबरी गांव का रहने वाला है। प्रवेश का यह वीडियो 10 दिन पुराना बताया जा रहा है।

इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ट्वीट पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ

नेता अरुण यादव ने ट्वीट किया है कि प्रवेश शुक्ला भारतीय जनता युवा मोर्चा में मंडल उपाध्यक्ष हैं। विधायक केदारनाथ शुक्ला ने उसे अपना प्रतिनिधि बनाया है। अपने ट्वीट में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल कुचवाही का एक पत्र भी संलग्न किया है, जिसमें प्रवेश शुक्ला का नाम चौथे नंबर पर है। लेटर पैड मंडल अध्यक्ष पुष्पराज सिंह चौहान के नाम से है। हालांकि इस लेटर पैड में दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर पूरे मामले को घोर निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

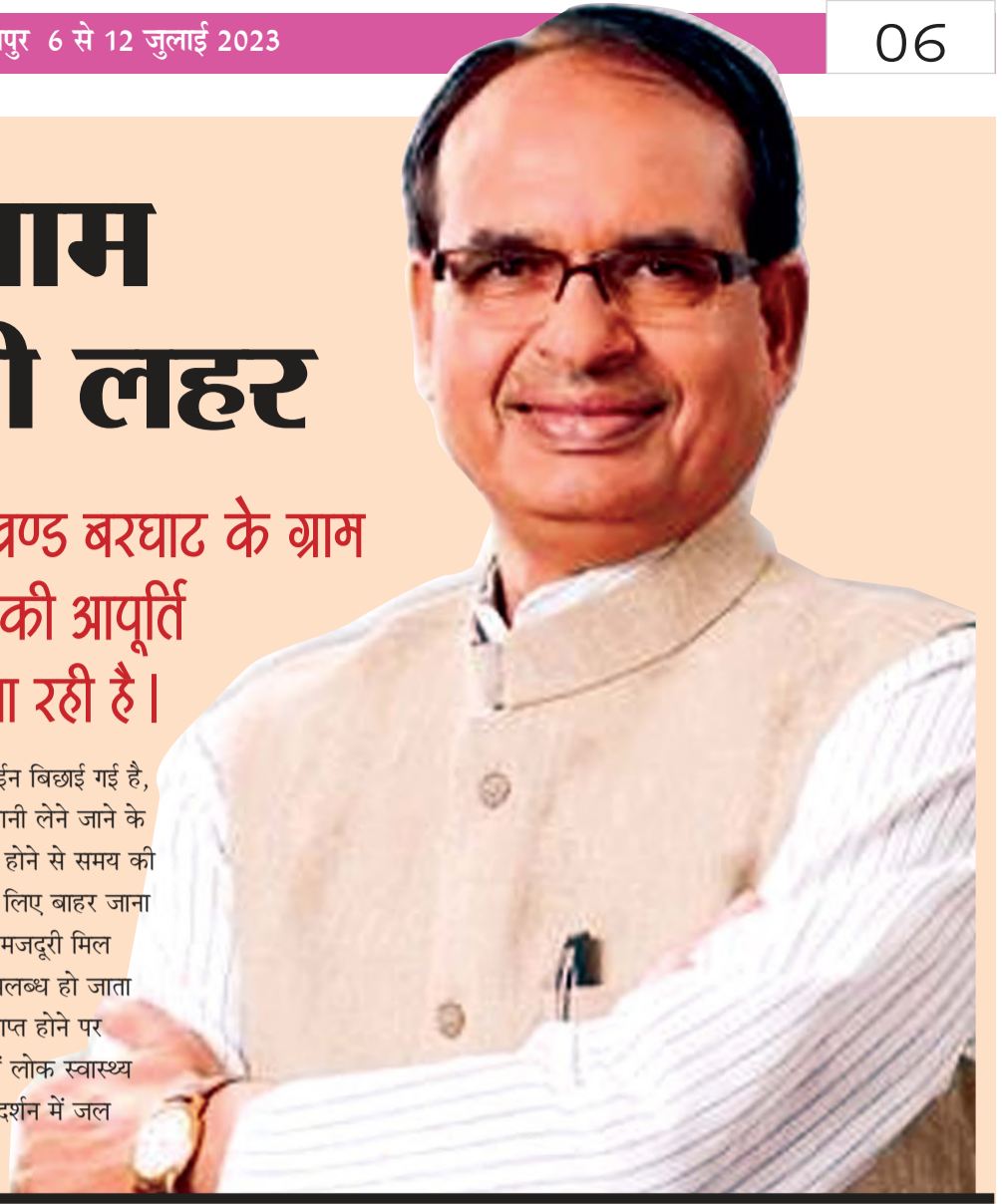
इसी बीच खबर मिली है कि बुधवार को प्रवेश के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी हो सकती है। पुलिस और राज्यस्व विभाग का अमला उसके घर पहुंच गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटेल ने बताया कि आरोपित को पुलिस टीम ने ग्राम खैरवावा के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस रात में ही थाने लेकर पहुंची। वह गमछे के सहारे बाहर भागने की फिफाक में था। पुलिस आरोपित से पूरे घटना को लेकर बारीकी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दीनदयाल साहू नामक व्यक्ति ने वह वीडियो बनाया था।



# जल जीवन मिशन से ग्राम जनमखारी में आई खुशी की लहर

जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के तहत विकासखण्ड बरघाट के ग्राम जनमखारी में 484 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय कर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। सरकार के इन प्रयासों की सराहना ग्रामीणों द्वारा की जा रही है।

**सिवनी।** योजना के तहत ग्राम जनमखारी में 20 हजार लीटर क्षमता की एक सम्मवेल और 1 लाख लीटर की टंकी बनाई गई तथा 5630 मीटर पाईप लाईन बिछाई गई है, जिसके माध्यम से ग्राम जनमखारी के सभी घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय निवासी श्रीमती निधि मरावी ने बताया कि पहले हैण्डपंप से पानी लेने जाने के लिए 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। जिससे समय के साथ-साथ कृषि कार्य प्रभावित होता था। उन्होंने कहा कि घर पर ही नल से जल उपलब्ध होने से समय की बचत हुई है, जिससे कृषि कार्य में सहूलियत मिली है। गांव की श्रीमती संतोषी बाई ने कहा कि वह मजदूरी करती है। पहले मजदूरी छोड़कर पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था और अक्सर लेट हो जाती थीं। किंतु अब पानी की सुविधा घर पर ही मिलने से अब वह मजदूरी के लिए समय पर जाती है और उसे अब पूरी मजदूरी मिल जाती है। ऐसे ही गांव की श्रीमती सुनीता ने कहा कि वह चाय की दुकान लगाती है। पहले पानी लाने हेतु ज्यादा समय लगता था। अब पानी घर पर ही उपलब्ध हो जाता है, घर पर पानी आने से समय पर चाय की दुकान लगाती है, जिससे परिवार का भरण-पोषण हो रहा है। ग्राम जनम खारी के प्रत्येक घर में नल से जल प्राप्त होने पर ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार ज्ञापित किया है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के मार्गदर्शन में जल जीवन मिशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन सिवनी जिले में तीव्र गति से संचालित है।



## शिवराज की 12 योजनाओं ने जीता जनता का दिल



मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं। 29 नवम्बर 2005 को वे राज्य के सीएन बने थे। 2003 में कांग्रेस का सफाया कर साता में आई बीजेपी सरकार के 2 साल में 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद सीएन शिवराज को मध्यप्रदेश की कमान सौंपी गई थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबू लाल गौर की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब से लेकर अब तक सीएन शिवराज ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं ने प्रदेश की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बरकरार रखी है। जिनके शिवराज सरकार के 12 सालों की वे 12 योजनाएं जिसने प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया।

**लाइली लक्ष्मी योजना :** लाइली लक्ष्मी योजना शिवराज सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। शिवराज सरकार इस योजना को अपनी महत्वपूर्ण अत्याधिक मानती है। साल 2006 में इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 22 लड़कों के जन्म के बाद, उसके नाम पर 22 साल, 6 हजार रुपये मूल्य के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदी करती है। इस योजना के तहत लड़की को छठी कक्षा में प्रवेश पर 2000 रुपये दिये जाते हैं, 9वीं कक्षा में प्रवेश पर 4000 रुपये दिये जाते हैं और बारहवीं कक्षा में प्रवेश पर 7500 रुपये दिये जाते हैं। बारहवीं और बारहवीं में पढ़ाई के दौरान उसे प्रति माह 200 रुपये दिये जाते हैं।

**मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना :** शिवराज सिंह चौहान की इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें घर की चीजों और सामूहिक दिवाह खर्च के लिए 15,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

**मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना :** इस अनूठी योजना के तहत किसी भी धर्म के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार के खर्च पर उनके पसंद के धार्मिक स्थानों का दौरा करने के सुविधा प्रदान की गई है।

**बेटी बचाओ अभियान :** बेटी बचाओ अभियान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। लड़कियों के लिंग अनुपात में जारी गिरावट को रोकना और उससे जुड़े सामाजिक असर और लड़कियों के शिक्षाक भेदभाव को दूर करना, इस अभियान के उद्देश्य हैं। इस अभियान के तहत समाज में एक स्वस्थ लिंग संतुलन के लिए कन्या भ्रूण को बचाने के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कई गतिविधियां चलाई गईं। लोक सेवाओं के प्रदान की गयी अभियान 2010 : मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010र नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है और ऐसा करने में विफलता के लिए जवाबदेही तंत्र की योजना करता है। इस अधिनियम के तहत, जाति, जन्म, विवाह और अधिवास प्रमाण पत्र जारी करना, पीने के पानी के कनेक्शन, राशन कार्ड, मू-अभिलेखों की प्रतियां जैसी 52 महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।

**मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना :** यह योजना 1 अप्रैल 2013 प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का श्रोत्र/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनागत हितधारियों को मार्गदर्शन सहायता व्याज अनुदान की सुविधा दी जाती है।

**अटल ज्योति अभियान :** आयोग क्षेत्रों के घरों में 24 घण्टे तथा खेती के लिये कम से कम 10 घंटे बिजली देने के लिये अटल ज्योति अभियान ताना किया गया। अभियान प्रदेश के सभी जिलों में ताना कर दिया गया है। भरपूर बिजली मिलने से गाँव में लघु और कुटीर श्रमों का जाल बिछने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बच मिलने की शुरुआत हो गई है।

**मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना :** इस योजना के तहत राज्य के 18 से 60 वर्ष आयु के श्रमिक मजदूरों के परिवार की स्त्री को प्रसूति व्यय पर छः सप्ताह की मजदूरी का मुआवजा, पति को पिछले अवकाश के साथ दो सप्ताह की मजदूरी का मुआवजा, बच्चों को पहली कक्षा से स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति, पाठ्यवी कक्षा तथा उसके आगे तब तक प्रथम श्रेणी में पास करने वाले विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार। विवाह सहायता योजना के तहत कन्याओं को नगद तथा आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत लाभ दिये जाते हैं।

**अन्नपूर्णा योजना :** मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना मध्यप्रदेश में अग्रतः, 2008 से लागू है। जून, 2013 से योजना में बीपीएल के साथ अंतर्वेद्य परिवार (अति गरीब परिवार) को भी शामिल किया गया। अब योजना में गैर एक रुपये और वावल दो रुपये कितो दिया जाने लगा। योजना में एपीएल परिवार को आयोडीनयुक्त नमक एक रुपये कितो प्रदाय किया गया। जनवरी, 2014 से योजना में एक रुपये कितो वावल, एक रुपये कितो गैर देहा प्रारंभ किया गया। मार्च, 2014 से पूरे प्रदेश में एक रुपये कितो की दर पर आयोडीनयुक्त नमक का प्रदाय प्रारंभ किया गया।

**मुख्यमंत्री छात्र गुरु योजना :** यह योजना मैट्रिकोत्तर स्तर के उन छात्रों के लिए है जिन्हें स्थानांतरण के कारण छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल पाता है, जबकि दूर से आने वाले विद्यार्थियों को आवास की तुरन्त आवश्यकता होती है, ऐसे छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा के अनुरूप छात्र गुरु योजना संचालित की जा रही है। **गावांदाय योजना :** प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का अति मूल्य प्रदान करने के लिये राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई यह महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत 2017-18 के समर्थन मूल्य तथा किसान के द्वारा कृषि उपज मंडी समिति के प्राणज में उपज विक्रय किये जाने पर पाए जाने वाले घोषित मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि को इस योजना प्रतिक्रिया के रूप में प्रदान किया जाएगा। 2017 की वायलट योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के बाद इस योजना को अगले फसल तक में क्रियान्वयन पर निर्णय लिया जायेगा।

# डेढ़ दशक में जन-सहयोग से विकसित राज्य के रूप में उभरा मध्यप्रदेश

देश के हृदय स्थल मध्यप्रदेश ने पिछले डेढ़ दशक में विकास के नये आयाम स्थापित कर विकसित राज्य की पहचान बना ली है। मध्यप्रदेश की सुशासन और विकास रिपोर्ट-2022 के अनुसार राज्य में आए बदलाव से मध्यप्रदेश बीमारू से विकसित प्रदेशों की पंक्ति में उदाहरण बन कर खड़ा हुआ है। इस महती उपलब्धि में प्रदेश में जन-भागीदारी से विकास के मॉडल ने अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में केन्द्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने मध्यप्रदेश को अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय बना दिया है। इस अरसे में सड़क, बिजली, पानी, कृषि, पर्यटन, जल-संवर्धन, सिंचाई, निवेश, स्व-रोजगार और अधो-संरचना विकास के साथ उन सभी पहलुओं पर सुविचारित एवं सर्वांगीण विकास की नवीन गाथा लिखी गई जो जन-कल्याण के साथ विकास के लिये जरूरी हैं।

बेहतर वित्तीय प्रबंधन और चौरफा विकास से आज प्रदेश की विकास दर 19.7 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है। देश की अर्थ-व्यवस्था में मध्यप्रदेश 4.6 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में बीते दशक में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर निरंतर बढ़ रही है। वर्ष 2001-02 में 4.43 प्रतिशत की दर आज बढ़ कर 16.43 प्रतिशत हो गई है प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 71 हजार 594 करोड़ रुपये से बढ़ कर 13 लाख 22 हजार 821 रुपये हो गया है। वर्ष 2001-02 में प्रति व्यक्ति आय 11 हजार 718 रुपये थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़ कर एक लाख 40 हजार 583 रुपये हो गई है। राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर विगत एक दशक में राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रही है।

विकास प्रक्रिया में अधो-संरचना के महत्व के महानजर मध्यप्रदेश में निरंतर अधो-संरचना विकास हो रहा है। अधो-संरचना बजट जो वर्ष 2002-03 में 3873 करोड़ रुपये था, वह वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 56 हजार 256 करोड़ रुपये हो गया है। एक समय था जब बिजली आती कम थी और जाती ज्यादा थी। आज प्रदेश बिजली क्षेत्र में आत्म-निर्भर है और 24 घंटे बिजली की उपलब्धता है। वर्ष 2003 में ऊर्जा क्षमता 5173 मेगावाट थी, जो बढ़ कर 28 हजार मेगावाट हो गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश अग्रणी है। ओंकारेश्वर में लगभग 3500 करोड़ के निवेश से 600 मेगावाट का प्लॉटिंग सोलर सोलर पावर प्लांट का कार्य प्रारंभ हो गया है। किसानों के खेतों में 50 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य है। विश्वधरोहर साँची बहुत जल्द सोलर सिटी के रूप में विकसित होकर देश में अपनी अलग पहचान बनायेगा।

अच्छी सड़कों विकास की धुरी होती है। एक समय था, तब यह पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्डे हैं या गड्डे में सड़क है। अब गाँव-गाँव, शहर-शहर अच्छी गुणवत्तायुक्त सड़कों का जाल बिछाया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2001-02 में 44 हजार किलोमीटर सड़कें थी, अब 4 लाख 10 हजार किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई के 40 हजार करोड़ की लागत के 35 कार्य स्वीकृत हैं। अटल, नर्मदा और विंध्य प्रगति पथ के साथ मालवा, बुंदेलखंड और मध्य विकास पथ निर्मित किए जा रहे हैं।



प्रदेश में सभी रेलवे क्रासिंग समाप्त करने के लिए 105 रेलवे ओवर ब्रिज के साथ 334 पुलों का निर्माण हो रहा है। साथ ही 86 हजार करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं के कार्य चल रहे हैं। वर्ष 2009 से 2014 के बीच जहाँ प्रदेश को औसतन 632 करोड़ रुपये का रेलवे बजट मिलता था, वहीं वर्ष 2022-23 में 13 हजार 607 करोड़ का रेलवे बजट प्रावधान मिला है, जो इक्कीस गुना अधिक है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे। अत्याधुनिक रानी कमलापति स्टेशन देश में एक मॉडल बना है। एक वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ हो चुकी है और आज प्रधानमंत्री श्री मोदी मध्यप्रदेश को 2 और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार भी निरंतर हो रहा है।

प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाना के लिए

सिंचाई क्षमताओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। वर्ष 2003 में सिंचाई क्षमता केवल 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2022 में बढ़ कर 45 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। वर्ष 2025 तक सिंचाई क्षमता को बढ़ा कर 65 लाख हेक्टेयर किये जाने पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। हर घर जल से नल योजना पर तेज गति से कार्य हो रहा है, अभी तक लगभग 50% घरों तक नल से जल पहुँच चुका है। आजादी के अमृत काल में प्रदेश में अब तक 5936 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है। केन-वेतवा लिक परियोजना के प्रथम चरण में बांध, लिक नहर तथा पाँवर हाउस का निर्माण कार्य इस वर्ष प्रारंभ होगा। अटल भू-जल योजना में भी लगभग 700 ग्राम पंचायतों में वॉटर सिक्युरिटी प्लान बनाए गए हैं।

उद्यमिकी फसलों का रकबा 4 लाख 67 हजार हेक्टेयर से बढ़ कर 25 लाख हेक्टेयर हो गया है। फसल उत्पादन 224 लाख मीट्रिक टन से बढ़ कर 725 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। फसल उत्पादकता 1195 किलोग्राम से बढ़ कर 2421 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। किसान-कल्याण के ध्येय से प्रदेश में गत 3 वर्षों में फसलों की नुकसानी पर 4000 करोड़ से अधिक की राहत राशि वितरित की गई है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक डिफाल्टर किसानों का 2123 करोड़ का ब्याज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना प्रारंभ की गई है। पिछले 3 वर्षों में किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं में 2 लाख 69 हजार 686 करोड़ रुपये से अधिक के हितलाभ वितरण किए गए हैं। फसल क्षति प्रतिपूर्ति दरों में भी कई गुना वृद्धि की गई है।

## शासन की योजना से प्राप्त मोटोइज्ड ट्रायसार्सिकल बनी दिव्यांग सुनील के व्यवसाय का जरिया

सिवनी। गरीब एवं असहाय जरूरतमंद लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा इनके बेहतर जीवनयापन के लिए प्रदेश सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाएँ बनाकर इन्हें युद्धस्तर पर क्रियान्वित कर रही है जिससे प्रत्यक्ष रूप से योजनाओं का लाभ इन असहाय गरीब परिवारों को मिल रहा है। ऐसे ही सिवनी नगरीय क्षेत्र मंगली पेठ निवासी सुनील बरमेया उम्र 30 वर्ष हैं, जो मोटोइज्ड ट्रायसार्सिकल से व्यवसाय कर अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। सुनील बरमेया बताते हैं कि 80 प्रतिशत पॉलीयो प्रस्त अस्थिबाधित दिव्यांग है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कक्षा आठवीं तक की ही पढाई कर पाए। साथ अपने भाई बहनों में सबसे बड़े होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी भी महसूस कर रहे थे, किंतु शारीरिक अक्षमता के कारण कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। सुनील बरमेया को उनकी अस्थिबाधित दिव्यांगता को देखते हुए सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा बैटरी चलित मोटोइज्ड ट्रायसार्सिकल प्रदान की गई, जिसके माध्यम से सुनील ने स्वयं का कुछ व्यवसाय करने की सोच लिए ट्रायसार्सिकल में आवश्यकतानुसार बदलाव कर कप रखने के लिए जगह बनाकर उत्साह से मोटोइज्ड ट्रायसार्सिकल में स्थानीय बाजार, मेला, हाट-बाजारों में जा-जा कर कप बेचने का व्यवसाय करने लगे, जिससे सुनील को प्रतिदिन 400 से 500 /- रुपये की आय प्राप्त हो जाती है। सुनील अपने परिवार की बखूबी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, एवं शासन की योजना से मिली मोटोइज्ड ट्रायसार्सिकल के लिए अत्यंत प्रसन्न हैं।











नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



मध्यप्रदेश शासन



शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

## मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना

# शिवराज सरकार की अनुपम सौगात सीखना-कमाना अब होगा साथ-साथ

- 46 क्षेत्रों के 800 से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण, इनमें विनिर्माण, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेल्वे, आईटी, साफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया, कला, कानूनी, विधि सेवाएं व अन्य सेवा क्षेत्र शामिल।
- 18 से 29 वर्ष के 10वीं-12वीं पास, आईटीआई, स्नातक व स्नातकोत्तर युवा पात्र।
- प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10 हजार रुपये तक स्टायपेंड।
- 15 जून से पंजीयन एवं 15 जुलाई से प्लेसमेंट।
- पंजीयन के लिए <https://mmsky.mp.gov.in/> पोर्टल विजिट करें।

D18417/23



मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी



मध्यप्रदेश शासन

आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2023